सांध्य दैनिक

श्रीकंचनपथ

RNI. Reg. No. CHHHIN/2009/30534
डाक पंजीयन क्रं.-छ.ग./दुर्ग/1000000029/2026-28

लीपा पोती नहीं सिर्फ सच

वर्ष- 17 अंक - 85 | www.shreekanchanpath.com | संस्थापक एवं प्रेरणास्रोत- स्व. श्रीमती रजनी अग्रवाल | भिलाई, बुधवार 07 जनवरी 2026 | पृष्ठ 8- मूल्य 1/-

सुकमा में 26 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, 13 माओवादियों पर था 65 लाख का इनाम, सात महिलाएं भी शामिल

श्रीकंचनपथ न्यूज

सुकमा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 26 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सरेंडर करने वाले माओवादियों में 13 पर कुल 65 लाख रुपए का इनाम था। सुकमा के पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण ने बताया कि इन कैडरों में सात महिलाएं भी शामिल हैं, जिन्होंने पूना मार्गेम पहल के तहत आत्मसमर्पण किया। यह सरकार की पुनर्वास नीति की सफलता है।

सुकमा के पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण ने ने बताया कि ये लोग माओवादियों की पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी बटालियन, दक्षिण बस्तर डिवीजन, माड़ डिवीजन और आंध्र ओडिशा सीमा डिवीजन में सक्रिय थे और अबूझमाड़, छत्तीसगढ़ के सुकमा और ओडिशा के सीमावर्ती इलाकों में कई घटनाओं में शामिल थे। ये माओवादी राज्य सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित थे जिसके तहत आत्मसमर्पण किया है।

लाली पर था दस लाख का इनाम

लाली उर्फमुचाकी आयते लखमू (35), जो एक कंपनी पार्टी समिति की सदस्य थी इस पर 10 लाख रुपये का इनाम था। मुचाकी हिंसा की कई बड़ी घटनाओं में शामिल थी, जिसमें 2017 में कोरापुट रोड (ओडिशा) पर एक वाहन को निशाना बनाकर आईईडी विस्फोट करना भी शामिल है, जिसमें 14 सुरक्षाकर्मियों की मौत हुई थी। चार अन्य प्रमुख कैडर - हेमला लखमा (41), अस्मिता उर्फकमलू सन्नी (20), रामबती उर्फ पदम जोगी (21) और सुंदरम पाले (20) इन चारों पर आठ-आठ लाख रुपये का इनाम था।

मिनपा हमले में शामिल था लखमा

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लखमा 2020 के मिनपा हमले में शामिल था, जिसमें 17 सुरक्षाकर्मियों की जान चली गई थी। आत्मसमर्पण करने वाले अन्य कैडरों में से तीन पर 5-5 लाख रुपये का इनाम था, एक कैडर पर तीन लाख रुपये, एक कैडर पर दो लाख रुपये और तीन कैडरों पर एक-एक लाख रुपये का इनाम था। आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों को 50,000 रुपये की सहायता दी गई है और उन्हें सरकार की नीति के अनुसार आगे पुनर्वासित किया जाएगा।

खास-खबर

भाजपा विधायक रेणुका सिंह के बेटे ने बाइक-सवार को मारी ठोकर

रायपुर। बीजेपी विधायक और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह के बेटे ने बाइक सवार को ठोकर मार दी। घटना 5 जनवरी की रात करीब डेढ़ बजे की है। अग्रसेन धाम चौक के पास कार सवार भाजपा विधायक रेणुका सिंह के बेटे बलवंत सिंह ने बाइक सवार त्रिभुवन सिंह ठाकुर को टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बाइक सवार चौक से गुजर रहा था, तभी तेज रफ्तार से आ रही कार बेकाबू होकर बाइक से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार सड़क पर दूर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायल को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो आरोपी की कार ही मिली, आरोपी भाग गया था। जिसके बाद उसके खिलाफ बीएनएस के तहत लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने का मामला दर्ज किया और 6 जनवरी की रात पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और थाने से उसे जमानत मिल गई।

भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधक और ठेकेदार के खिलाफ केस दर्ज

भिलाई। भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) टाउनशिप क्षेत्र में बिना सुरक्षा उपकरण काम के दौरान एक ठेका श्रमिक हादसे का शिकार हुआ है। आरोप है कि ठेकेदार ने उसे जबरदस्ती झुके हुए पोल पर चढ़ाया, जहां से गिरने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित ने ये भी आरोप लगाया है कि प्रबंधन ने ठीक से उसका इलाज भी नहीं कराया। ठेकेदार ने मुआवजा देने और स्वस्थ होने पर काम पर वापस रखने का आश्वासन दिया था, लेकिन चार महीने बाद भी उसे न तो मुआवजा मिला और न ही किसी कोई सहायता मिली। मामला भिलाई नगर थाना क्षेत्र का है। दुर्ग स्क्क को दी गई लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने बीएसपी प्रबंधक राजकिशोर, दिलीप राणे, टिकेंद्र ठाकुर, अशोक साहू, महिपाल देशमुख, ठेकेदार शंकर दयाल सिंह के खिलाफ धारा 289, 125 (बी) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।

ट्रैक को पार करने के दौरान ट्रेन की चपेट में आई महिला की मौत

जगदलपुर। दंतेवाड़ा जिले के कटेकल्याण थाना क्षेत्र के ग्राम कावड़गाँव के पास एक महिला रेलवे ट्रेक को पार करने के दौरान अचानक उसकी चपेट में आ गई, इस घटना में घायल महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। इस मामले में ग्रामीणों ने बताया कि केके रेललाइन पर महिला को ट्रेन आती दिखाई नहीं दी और वह उसकी चपेट में आ गई। इस घटना में घायल महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं, महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं, पुलिस आसपास के गांवों में महिला की पहचान करने में जुटी है। वहीं, महिला के पास से किसी भी तरह से कोई भी दस्तावेज नहीं मिले हैं. जिससे कि उसकी पहचान हो सके।

छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 की तैयारियां तेज

केंद्र सरकार ने गृह विभाग को बनाया नोडल, सरकार करेगी डिजिटल गणना

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति (एसएलसीसीसी) की प्रथम बैठक मुख्य सचिव विकास शील की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बार की यह गणना डिजिटल पैटर्न पर होगी। बैठक में बताया गया कि छत्तीसगढ़ में जनगणना के लिए गृह विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा और भारत सरकार, जनगणना निदेशालय तथा राज्य के सभी विभागों के बीच समन्वय की जिम्मेदारी निभाएगा।

निदेशक जनगणना कार्तिकेय गोयल ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जनगणना 2027 की रूपरेखा, डिजिटल रोडमैप और संगठनात्मक ढांचे की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जनगणना 2027 देश की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी। डेटा संग्रह मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जाएगा, जबकि निगरानी और प्रबंधन वेब पोर्टल से होगा। इस बार नागरिकों को स्व-गणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) की सुविधा भी मिलेगी, जिससे वे अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे।

बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि जनगणना जैसे बड़े काम के लिए राज्य में लगभग 63 हजार प्रगणकों और पर्यवेक्षकों सहित बड़ी संख्या में प्रशासनिक कार्मिकों की आवश्यकता होगी। जनगणना के पहले चरण से पहले पूर्व-परीक्षण का कार्य नवंबर 2025 में कबीरधाम जिले के कुकदूर, महासमुंद जिले की महासमुंद तहसील के चयनित ग्रामों और रायपुर के एक वार्ड में किया जा चुका है। इन अनुभवों को आगामी जनगणना में शामिल किया जाएगा।

1 अप्रैल से होगी गणना

मुख्य सचिव ने बताया कि जनगणना 2027 के पहले चरण में 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 के बीच 30 दिनों की अवधि में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना होगी। मानसून और स्कूल शिक्षा को ध्यान में रखते हुए अवधि तय करने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरे चरण में फ़रवरी 2027 में देशभर में एक साथ जनसंख्या गणना होगी, जिसके मद्देनज़र स्कूल शिक्षा विभाग को शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करने के निर्देश दिए गए।

सरकार ने की सक्रिय सहयोग की अपील

मुख्य सचिव विकास शील ने कहा कि जनगणना 2027 राज्य के भविष्य की नीतियों, योजनाओं एवं संसाधन आवंटन की आधारशिला है। उन्होंने अपेक्षा व्यक्त की कि सभी विभाग साझा उत्तरदायित्व और समन्वित प्रयास के साथ इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य को मिशन मोड में पूरा करेंगे। उन्होंने जनता से भी अपील की कि वे स्व-गणना एवं प्रत्यक्ष गणना दोनों प्रक्रियाओं में सक्रिय सहयोग प्रदान करें, ताकि छत्तीसगढ़ राज्य में जनगणना 2027 का कार्य पूर्णतः सटीक, पारदर्शी एवं समयबद्ध रूप में सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह एवं राज्य नोडल अधिकारी (जनगणना) मनोज पिंगुआ, निदेशक जनगणना कार्य निदेशालय कार्तिकेय गोयल, एनआईसी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

छत्तीसगढ़ में ठंड से ठिठुरन, चार जिलों में 10 जनवरी तक स्कूल बंद

अधिकांश जिलों में सामान्य से नीचे तापमान

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अधिकांश जिलों में रात का तापमान सामान्य से नीचे चला गया है। प्रदेश में मैनपाट सबसे ठंडा बना हुआ है, यहां न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री पहुंच गया है। यहां ओंस की बूंदें जमने लगी हैं।

अंबिकापुर में रात का पारा 3.8एष्ट दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 5 डिग्री कम है। मैदानी इलाकों में रायपुर सबसे ठंडा रहा, जहां रात का पारा 7एष्ट तक गिर गया। दुर्ग में 7 डिग्री और पेंड्रा रोड में 7.2 डिग्री रहा। इस बीच मौसम विभाग ने 17 जिलों में शीतलहर का यलो अलर्ट और 15 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। दोनों अलर्ट के साथ हेल्थ एडवाइजरी भी जारी की गई है।

4 जिलों में स्कूल बंद

सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड को देखते हुए चार जिलों में प्राइमरी स्कूल 10 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। सरगुजा और बलरामपुर के बाद मंगलवार देर शाम कोरिया और सूरजपुर जिलों में भी प्राइमरी स्कूलों को 10 जनवरी तक बंद करने का आदेश जारी हो गया है। मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों का संचालन पूर्ववत जारी रहेगा। ठंड के कारण दो पालियों में संचालित होने वाली कक्षाओं का समय बदल दिया गया है।

प्राकृतिक आपदा पीड़ित के वारिसों को प्रशासन द्वारा दी गई 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि

श्रीकंचनपथ न्यूज

कोण्डागांव। कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा पीड़ित के 5 प्रकरणों में वारिसों को 20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि प्रदान की गयी।

कलेक्टर द्वारा कोण्डागांव तहसील के डी.एन.के. निवासी कुमुद सोनानी की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर पत्नी गंगा सोनानी को 4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि, कोण्डागांव तहसील के ग्राम चेरंग निवासी लालूराम की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर पुत्री सुमित्रा, पुत्र सुनील, अनिल भाई मलसाय को 4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि, बड़ेराजपुर तहसील के ग्राम कोंगेरा निवासी सरजूराम की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर पत्नी सामबाई, पुत्र प्रीतम, पुत्री प्रतिमा, पिता हरिराम को 4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि, बड़ेराजपुर तहसील के ग्राम किबड़ा निवासी रामसाय की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर पत्नी सुरेखा को 4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि, कोण्डागांव तहसील के ग्राम पल्ली निवासी रामूराम मरकाम की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर पत्नी रतनी बाई मरकाम को 4 लाख की राशि प्रदान की गयी है।

खरीदी केंद्र में मिला मिलावटी धान

बेमेतरा। बेमेतरा में धान खरीदी जारी है। इस बीच यहां के धान उपार्जन केंद्र ग्राम गाड़ाडीह में मिलावट का मामला सामने आया है। दरअसल, जिला प्रशासन की टीम द्वारा उपार्जन केंद्र में रखे गए 5 स्टैक मोटा धान की जांच की गई, जिसमें पुराना धान व अमानक श्रेणी का नया धान मिश्रित रूप में पाया गया। गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर टीम ने कुल 10 हजार बोरे धान को अस्थायी रूप से जब्त कर उनके परिवहन पर रोक लगा दी है।

बेमेतरा में आयोग को मिले 12 हजार से ज्यादा संदिग्ध मतदाता

बेमेतरा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में हाल में हुए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) अंतर्गत 12 हजार 339 मतदाता संदिग्ध मिले हैं। इन मतदाताओं को अब दस्तावेज दिखाने होंगे। ऐसे लोगों को आयोग के ईआरओ/एईआरओ ने नोटिस जारी कर दिया है।

दरअसल, ये वो लोग है जो, सर्वे के दौरान जिले के तीन विधानसभा क्षेत्र में नो-मैपिंग श्रेणी में आए हैं। इनके परिजन का नाम 2003 की सूची में नहीं है। इन

वोटर्स को निर्वाचक नामावली में अपना नाम बनाए रखने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आवश्यक दस्तावेज के साथ नियत तिथि, समय व स्थान पर संबंधित अधिकारी के समक्ष सुनवाई में उपस्थित होने के निर्देश दिए है। इसमें विधानसभा क्षेत्र साजा में 2 हजार 808, बेमेतरा में 3 हजार 715 व नवागढ़ में 5 हजार 816 वोटर्स है। ये वर्ष 2003 की मतदाता सूची में अपना अथवा माता/पिता का नाम शामिल होने से संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं। बता दें कि जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र में कुल 8 लाख एक हजार 756 मतदाता पंजीकृत थे। गणना पत्रकों के परीक्षण के बाद 7 लाख 16 हजार 635 मतदाता के नाम प्रारंभिक मतदाता सूची में शामिल किए गए है।

शिक्षक के नाम पर लाखों का लोन लेकर धोखाधड़ी

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक सरकारी शिक्षक के साथ लाखों रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एक आरोपी ने शिक्षक के नाम पर विभिन्न बैंकों से बड़ी रकम का लोन निकाला और फिर किस्तों का भुगतान बंद कर दिया। पीड़ित शिक्षक की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की गई है।

यह घटना खरसिया थाना क्षेत्र में हुई है, जहां शिक्षक लोकनाथ रात्रे ने अपनी शिकायत में बताया कि उनका परिचय ग्राम सपिया निवासी विद्याचरण गोरे से था, और

उनके मामा गिरीश कुमार जोल्हे ने मई 2024 में उनसे संपर्क किया। गिरीश कुमार ने शिक्षक को विश्वास में लेकर उनके नाम पर लोन निकालने और किस्तों का भुगतान स्वयं करने का प्रस्ताव दिया, जिसके बदले में 35 प्रतिशत राशि देने का वादा किया। शिक्षक के दस्तावेजों का दुरुपयोग करते हुए, गिरीश कुमार जोल्हे ने चोला मण्डलम, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक और भारतीय स्टेट बैंक से कुल 27 लाख 25 हजार रुपये का लोन निकाला। लोन की रकम शिक्षक के खाते में आई, जिसे आरोपी ने अपने खातों में ट्रांसफर कर लिया। शुरुआत में कुछ महीनों तक किस्तों का भुगतान करने के बाद, आरोपी ने अचानक भुगतान बंद कर दिया। जिसके बाद अब शिक्षक ने धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी गिरीश कुमार जोल्हे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

सिम्स में 4 मरीजों का सफल कॉर्निया प्रत्यारोपण

श्रीकंचनपथ न्यूज

बिलासपुर। बिलासपुर के छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) के नेत्र रोग विभाग ने चार मरीजों का सफल कॉर्निया प्रत्यारोपण किया है। इस जटिल शल्यक्रिया के बाद चारों मरीजों की आंखों की रोशनी लौट आई है, जिससे उनके जीवन में नया उजाला आया है। अस्पताल में भर्ती किए गए ये चारों मरीज (दो महिलाएं और दो पुरुष, जिनकी उम्र 35 से 50 वर्ष के बीच है) बिलासपुर जिले के निवासी हैं। वे सभी 'फंगल कॉर्नियल अल्सर' से पीड़ित थे।

यह संक्रमण धान की कटाई के दौरान आंखों में

चोट लगने के कारण हुआ था। मरीजों की आंखों में संक्रमण इतना गंभीर था कि पुतली पूरी तरह सफेद हो गई थी। असहनीय दर्द के कारण आंखों को निकालने तक की स्थिति बन गई थी। विभागाध्यक्ष डॉ. सुचिता सिंह और डॉ. प्रभा सोनवानी के नेतृत्व में मरीजों को पहले संक्रमण रोकने का उपचार दिया गया।

इसके बाद आई बैंक से प्राप्त नेत्रदान की मदद से सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया गया। सिम्स के अधिष्ठाता डॉ. रमणेश मूर्ति ने बताया कि संस्थान में चिकित्सा सेवाओं को लगातार आधुनिक और सुलभ बनाया जा रहा है। उन्होंने नेत्र रोग विभाग की इस सफलता को टीम वर्क का परिणाम बताया।

यातायात सुरक्षा; नौ दिन चले अढ़ाई कोस

यातायात किसी भी देश के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। खासकर तब जब उस देश के नागरिकों में और मवेशियों में कोई ज्यादा अन्तर न हो। शायद इसीलिए यातायात को किसी भी देश की शिक्षा, सभ्यता और संस्कृति का पैमाना भी माना जाता है। विश्व में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों के सबसे अधिक मामले भारत से सामने आते हैं, जहां प्रति वर्ष 1.5 लाख से अधिक मौतें होती हैं। इसा लिहाज से इसे दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक माना जाता है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि यह देश के आबादी घनत्व के कारण है। वैसे आम लोगों का मानना है कि देश में यातायात के प्रति चेतना लुप्त प्राय है। इसे सुधारने के लिए 1989 में भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ट्रैफिक सप्ताह (राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह) की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात नियमों के पालन और सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। इसे हर साल 11 से 17 जनवरी के बीच मनाया जाता है। पर इसका नतीजा ढाक के तान पात जैसा ही है। देश में मनाए जाने वाले किसी भी अन्य दिवस या सप्ताह की तरह यह भी एक उत्सव की तरह है। इस दौरान स्कूली बच्चों को ट्रैफिक के नियमों की जानकारी दी जाती है। लेफ्ट राइट का कांसेप्ट सिखाया जाता है। पर आजकल इसका पूरा जोर हेल्मेट और सीट बेल्ट पर है। वैसे भी हमारा यहां ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक ठीक करने नहीं बल्कि दस्तावेजों की जांच करने के लिए सड़कों पर उतरती है। वैसे भी उसका मूल काम उद्देश्य राजस्व इकट्ठा करना है। ट्रैफिक का क्या है, जो सड़क पर उतरेगा, वह भुगत लेगा। मैदान में ड्राइविंग सीखने वाला सड़क पर भी बिंदास रहे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सड़क अच्छी बना दो तो रफ्तार बढ़ जाती है, चौड़ी कर दो वो और चौड़े हो जाते हैं। 1970-80 के दशक में जब गाड़ियों की संख्या कम थी, लोग स्वतः यातायात नियमों का पालन करते थे। पता नहीं यातायात पुलिस ने ऐसा क्या किया कि ज्यों-ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता ही चला गया।

फैमिली कोर्ट के रवैए पर हाईकोर्ट नाराज

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस संजय जायसवाल की डिवीजन बेंच ने पारिवारिक विवादों के मामले में फैमिली कोर्ट की जवाबदेही को लेकर महत्वपूर्ण फैसला दिया है। डिवीजन बेंच ने कहा कि, अगर कोई पक्षकार खासकर महिलाएं या आर्थिक रूप से कमजोर पक्ष वकील करने में असमर्थ है, तो फैमिली कोर्ट की यह जिम्मेदारी है कि उसे तत्काल कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाए। सिर्फ यह कह देना कि, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जाकर आवेदन दें, यह उचित नहीं है। फैमिली कोर्ट की जिम्मेदारी केवल मामले निपटाना नहीं, बल्कि महिलाओं और बच्चों को न्याय दिलाना महत्वपूर्ण है। हाईकोर्ट ने प्रकरण में फैमिली कोर्ट को महिला के तलाक के केस की दोबारा सुनवाई करने का आदेश भी दिया है।

संपादकीय

पंजाब में बढ़ते अपराध

कानून व्यवस्था की पोल खोलती हत्याएं

यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि पंजाब में सरेआम की जा रही लक्षित हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दुस्साहसी हत्यारे अपने मंसूबों को अंजाम देकर साफ निकल जाते हैं। यह विडंबना ही है कि पंजाब में नये साल की शुरुआत दिनदहाड़े हुई हत्याओं की एक शृंखला के साथ हुई है। अब चाहे लुधियाना जिले में एक पूर्व कबड्डी खिलाड़ी की निर्मम हत्या हो या अमृतसर के मैरिज रिसॉर्ट में एक विधायक के करीबी सरपंच की गोली मारकर बेरहमी से हत्या, इनसे पता चलता है कि पंजाब के अपराधियों में कानून का भय नहीं रह गया। निश्चित रूप से ये घटनाएं पंजाब में गंभीर चुनौती बनती एक जटिल समस्या की ओर इशारा करती हैं। इस चिंताजनक होती स्थिति की वजह लगातार अपराधी गिरोहों के नेटवर्क का मजबूत होना, घातक हथियारों की सहज उपलब्धता और पुलिस बल पर लगातार बढ़ता दबाव भी है। दूसरी ओर विपक्षी दल आरोप-प्रत्यारोपों का सिलसिला चलाए रहते हैं और राजनीतिक लक्ष्यों के लिये मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग करते रहते हैं। वहीं सरकार इस संकट को अपने पूर्ववर्तियों द्वारा विरासत में छोड़ा गया बताते हैं। लेकिन एक हकीकत है कि इन बयानबाजियों से नागरिकों की असुरक्षा कम नहीं होती है। वहीं पंजाब के शीर्ष पुलिस अधिकारियों की दलील होती है कि पंजाब में अपराध दर राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। लेकिन राज्य में बढ़ते अपराधों के संकट को किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से जब हत्याएं राज्य के भीड़भाड़ वाले इलाकों में होती हैं तो लोगों का कानून व्यवस्था से भरोसा उठ जाता है। वहीं दूसरी ओर राज्य के पुलिस महानिदेशक की दलील है कि पाकिस्तान की खुफ्फिया एजेंसी आईएसआई ड्रोन के जरिये हथियार, गोला-बारूद और नशीले पदार्थ भेजकर सीमांत राज्य पंजाब के खिलाफ परोक्ष युद्ध छेड़े हुए है। निश्चय ही यह बात इस सीमावर्ती राज्य के लिये गंभीर चिंता का विषय है।

> “ निश्चित रूप से ये घटनाएं पंजाब में गंभीर चुनौती बनती एक जटिल समस्या की ओर इशारा करती हैं। इस चिंताजनक होती स्थिति की वजह लगातार अपराधी गिरोहों के नेटवर्क का मजबूत होना, घातक हथियारों की सहज उपलब्धता और पुलिस बल पर लगातार बढ़ता दबाव भी है। दूसरी ओर विपक्षी दल आरोप-प्रत्यारोपों का सिलसिला चलाए रहते हैं और राजनीतिक लक्ष्यों के लिये मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग करते रहते हैं। वहीं सरकार इस संकट को अपने पूर्ववर्तियों द्वारा विरासत में छोड़ा गया बताते हैं।

इसमें दो राय नहीं कि पंजाब के डीजीपी का पाक से अपराधियों को प्रश्रय देने वाला बयान चिंता बढ़ाने वाला है। खासकर उस राज्य के लिये, जिसने एक दशक तक उग्रवाद का सामना किया हो। लेकिन पंजाब के अपराध संकट के लिये केवल बाहरी कारकों को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। यह पुलिस विभाग की शिथिलता व खुफ्फिया तंत्र की नाकामी के साथ सामाजिक विद्रूपताओं से भी उपजा संकट है। निस्संदेह, राज्य में अधिक बेरोजगारी है। बंदूक संस्कृति का महिमामंडन भी गंभीर चुनौती है। वहीं दूसरी ओर युवाओं में रातों-रात धनवान बनने का लालच भी स्थानीय व क्षेत्रीय गिरोहों के पनपने की गंभीर वजह है। इसके अलावा पुलिस विभाग की संरचना की भी कुछ विसंगतियां सामने आती हैं। मसलन पुलिस व्यवस्था में उच्च अधिकारियों की तो अधिकता है मगर फील्ड स्टाफ पर काम का बोझ जरूरत से ज्यादा है। इसके अलावा पुलिस के कामकाज में राजनीतिक हस्तक्षेप के भी आरोप लगते रहे हैं। यही वजह है कि पुलिस, हासिल कुछ सफ्लताओं के बावजूद जनता का विश्वास जीतने के लिये संघर्ष कर रही है। लेकिन राजनीतिक बयानबाजियों से इतर राज्य सरकार को अपनी रणनीति में बदलाव लाकर धरातल पर गंभीर प्रयास करने होंगे। मौजूदा हालात में बहुआयामी रणनीति बनाने की सख्त जरूरत महसूस की जा रही है। इसके अंतर्गत पुलिस सुधार भी प्राथमिकता के आधार पर किए जाने की जरूरत है, ताकि हाइटैक अपराधियों पर शिकंजा कसा जा सके। इसके साथ ही अपराध नियंत्रण में केंद्रीय एजेंसियों से बेहतर तालमेल करने की भी जरूरत है। इसके अलावा बंदूकों पर लगाम लगाने के लिये कानून को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता होगी। राज्य में रोजगार के अवसरों में वृद्धि, कौशल विकास में व्यापक निवेश करने तथा भटके हुए युवाओं को मुख्यधारा में लाने के प्रयास योजनाबद्ध ढंग से करने होंगे। ऐसे राज्य में जो एक दशक तक चरमपंथ की त्रासदी झेल चुका हो, अपराधियों के खिलाफ बड़ी मुहिम वक्त की मांग है। राज्य के सत्ताधीशों को चाहिए कि पंजाब द्वारा कड़ी मेहनत से हासिल की गई शांति को गैंगस्टरों, ड्रग माफ्फिया और आतंकवादियों के घातक गठजोड़ का शिकार कदापि नहीं होने दें।

रोजगार गारंटी में सुधार

भावनाओं के बजाय तथ्यों पर आधारित हो बहस

शैलेश कुमार सिंह

लोकतंत्र में लोकनीति पर सार्वजनिक बहस स्वाभाविक ही नहीं, बल्कि जरूरी भी है। आजीविकाओं (खास तौर से ग्रामीण परिवारों के लिए) को आकार देने वाले कानूनों की कड़ाई से समीक्षा की ही जानी चाहिए। लेकिन इस तरह की समीक्षा नए कानून के प्रावधानों के सावधानी पूर्वक अध्ययन पर आधारित होनी चाहिए। यह पिछले फ्रेमवर्क से निकाले गए अनुमानों या नुकसान के भय पर आधारित नहीं होनी चाहिए। मगर विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) कानून 2025 की ज्यादातर आलोचनाएं इस जाल में फंस जाती हैं। इनमें जल्दबाजी में पिछली नाकामियों का विश्लेषण कर उनका ठीकरा सुधार पर ही फोड़ दिया जाता है।

दो दशक पहले बनाए गए रोजगार गारंटी कानून ने ग्रामीण आय को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और संकट के वक्त सुरक्षा प्रदान की। कोविड की वैश्विक महामारी जैसे संकट के समय में इसके योगदान को स्वीकार किया गया है। लेकिन समय के साथ अनुभव से इसकी दीर्घकालिक ढांचागत कमियां भी उजागर हुई हैं। मजदूरी के भुगतान में बार-बार देरी हो रही थी। प्रक्रियात्मक अवरोधों ने बेरोजगारी भत्ते को अप्रभावी बना दिया था। विभिन्न राज्यों में इस योजना तक पहुंच में काफी अंतर था। प्रशासनिक क्षमता असमान थी तथा फर्जी जॉब कार्ड, उपस्थिति के रजिस्टर में हेरफेर और खराब गुणवत्ता वाली संपदाओं के सृजन से बड़े पैमाने पर धन की बर्बादी हुई। ये छोटी नहीं, बल्कि प्रक्रियात्मक खामियां थीं। इसलिए मुख्य मुद्दा यह नहीं है कि क्या सुधार की जरूरत थी। मुद्दा यह है कि क्या नए फ्रेमवर्क में इन खामियों को सार्थक ढंग से दूर किया गया है। आम दावा है कि नए कानून में बुनियादी कमियां तो बनीं रहीं और समूची बहस को संक्षिप्ताक्षरों की होड़ में समेट दिया गया। लेकिन हकीकत में इसका उलट ही सच के ज्यादा करीब है। नया कानून डिलीवरी की उन कमियों को दूर करने पर केंद्रित है जिनकी वजह से पिछले फ्रेमवर्क की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा था। कमजोर परंपरागत प्रणालियों की जगह सत्यापित कामगार पंजीकरण ने ले ली है। देरी के लिए स्वत: मुआवजे के प्रावधान के साथ मजदूरी भुगतान की वैधानिक समय सीमाएं तय की गई हैं। अयोग्यता के उन प्रक्रियात्मक प्रावधानों को खत्म कर दिया गया है जिनकी वजह से बेरोजगारी भत्ता अप्रभावी बन गया था। स्पष्ट समयसीमा और जवाबदेही के साथ शिकायत निवारण को मजबूत किया गया है। ये दिखावटी बदलाव नहीं हैं। ये उन खामियों को दूर करते हैं जिनसे कामगारों का विश्वास टूटता था।

एक अन्य आलोचना यह है कि रोजगार गारंटी को खत्म कर दिया गया है। इनके अनुसार नई योजना में पुरानी कमजोरियां बनी हुई हैं। इस तरह की आलोचना सही नहीं है। वेतन रोजगार के कानूनी अधिकार को बरकरार और न्यायसंगत रखा गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह कि रोजगार की वैधानिक पात्रता को 100 दिनों से बढ़ाते हुए 125 दिन कर दिया गया है। बदलाव क्रियान्वयन की संरचना में किया गया है। पुराने कानून का मॉडल टुकड़ों में बंटा हुआ और प्रतिक्रियात्मक था। यह अक्सर संकट शुरू हो जाने के बाद ही हरकत में आता था। नए कानून का फ्रेमवर्क योजनाबद्ध और लागू करने योग्य है। इसे पूर्वानुमान के आधार पर कार्य सौंपे जाने के लिए डिजाइन किया गया है। वैधानिक सुधार के जरिए क्रियान्वयन की नाकामियों को दूर किए जाने को दोहराव नहीं, बल्कि संशोधन माना जाना चाहिए।

बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे अधिक गरीब आबादी वाले राज्यों को पहले के फ्रेमवर्क के तहत सबसे कम लाभ मिलने के सम्बन्ध में जो चिंताएं जताई गई हैं, वे सही हैं लेकिन यह बात सुधार की जरूरत को और मजबूत करती है, न कि उसे कमजोर करती है। इन राज्यों में मनरेगा का लाभ कम पहुंचा यह योजना की एक बड़ी विफ्लता थी। बिना किसी ठोस योजना के सिर्फ मांग के आधार पर चलने वाला मॉडल उन राज्यों के पक्ष में रहा जिनकी प्रशासनिक क्षमता बेहतर थी, जबकि अधिक जरूरत और पलायन वाले राज्य पिछड़ गए। नया फ्रेमवर्क सीधे तौर पर इस असंतुलन को दूर करता है, यह रोजगार पैदा करने के काम को 'विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं' से जोड़ता है, जहाँ स्थानीय मांग और कामों की पहले से मंजूरी को सुनिश्चित फंडिंग के साथ मिलाया जाता है। असमान वितरण ही सुधार की ज़रूरत की असली वजह थी; पुरानी व्यवस्था को बनाए रखने का मतलब केवल मौजूदा असमानताओं को और बढ़ाना होता। इसके अलावा, निष्पक्ष मानकों पर आधारित आवंटन से राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे में अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता आएगी।

आलोचना का एक पक्ष यह भी है कि 125 दिनों का रोजगार देने का विस्तार केवल दिखावा है, क्योंकि अब राज्यों को भी खर्च का एक हिस्सा उठाना होगा। यह तर्क पहले के उदाहरणों और सुरक्षा उपायों दोनों को नज़रअंदाज़ करता है। केंद्र और राज्यों के बीच खर्च बांटने का यह तरीका केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के पुराने नियमों के अनुसार ही रखा गया है। वहीं, उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर के लिए 90:10 के अनुपात (जहाँ केंद्र 90 और राज्य 10 प्रतिशत खर्च उठाते हैं) को जारी रखा गया है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि योजना बनाकर काम करने से पैसों का बेहतर इस्तेमाल होता है, जिससे अनिश्चितता खत्म होती है और योजना को लागू करने में कम रुकावटें आती हैं। अधिकारों का दायरा बढ़ाना और साझा जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल को दर्शाता है, न कि कमज़ोरी को। ग्रामीण सड़कों से लेकर, आवास और पीने के पानी जैसे कई सफ्ल राष्ट्रीय कार्यक्रम भी इसी तरह की व्यवस्था के तहत काम करते हैं।

आर्थिक रूप से कमज़ोर राज्यों को अक्सर नए फ्रेमवर्क का संभावित शिकार बताया जाता है। लेकिन सिर्फ़ आर्थिक कमज़ोरी ही राज्यों के बाहर होने का कारण नहीं है। पिछली व्यवस्था के तहत, राज्यों का इस योजना से बाहर होना अक्सर खराब प्लानिंग, सरकारी मशीनरी की कम क्षमता और काम करने के तरीके में आने वाली रुकावटों की वजह से था। नया कानून पहले से की गई तैयारी, जनता की भागीदारी और प्रौद्योगिकी के जरिये जोखिमों को कम करने की कोशिश करता है। नयी व्यवस्था में एक बार योजना मंजूर होने के बाद, काम देने से मना करने की अधिकारियों की शक्ति को कम किया गया है और पारदर्शिता तथा जवाबदेही को मजबूत किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रशासनिक खर्च को 6त्न से बढ़ाकर 9त्न कर दिया गया है जिससे राज्य अपनी जमीनी क्षमता को कार्यक्रम की विशालता के अनुरूप मजबूत बना सकें। किसी राज्य विशेष की अपनी चुनौतियाँ उस राष्ट्रीय सुधार को गलत साबित नहीं करतीं, इसका उद्देश्य पूरी व्यवस्था की कमजोरियों को ठीक करना है।

पुरानी 'मांग-आधारित' योजना और नई 'आपूर्ति-आधारित' योजना के बीच के अंतर को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है। व्यवहार में, यह अंतर इतना बड़ा नहीं है। नया फ्रेमवर्क डिमांड को कम नहीं करता; बल्कि यह योजना के माध्यम से इसे एक संस्थागत रूप देता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मांगी गई मांग को पूरा भी किया जा सके। संसाधनों के भरोसे के साथ की गई एक नियोजित मांग, उस सैद्धांतिक अधिकार से कहीं ज्यादा सशक्त है जो कभी पूरा ही नहीं हो पाता। रोजगार गारंटी का अधिकार-आधारित स्वरूप, कमजोर होने के बजाय और मजबूत हुआ है। काम के दिनों को बढ़ाकर 125 दिन करना, मजदूरी भुगतान के लिए कानूनी रूप से लागू समय-सीमा, देरी होने पर अपने-आप मिलने वाला मुआवजा, हक छीनने वाली शर्तों को हटाना, और शिकायत निवारण के लिए अपील की सुविधा—ये सब मिलकर 'काम के अधिकार' की व्यावहारिक उपयोगिता को बढ़ाते हैं। अधिकार सबसे ज़्यादा तब मायने रखते हैं जब उनका प्रशासनिक बाधाओं के बिना इस्तेमाल किया जा सके। यहां तक कि आलोचक भी मानते हैं कि योजना को लागू करने की विफ्लताएं—जैसे भ्रष्टाचार, फर्जी जॉब कार्ड, उपस्थिति रजिस्टर में हेरफेर और खराब गुणवत्ता वाली संपदाओं का निर्माण, पुराने फ्रेमवर्क की सबसे बड़ी कमजोरियां थीं। यह सुधार इन्हीं विफ्लताओं को दूर करने की कोशिश करता है, जिसके लिए सत्यापित लाभार्थी प्रणाली, मजबूत ऑडिट और अन्य योजनाओं के साथ मिलकर संपदा निर्माण का सहारा लिया गया है।

कुल मिलाकर, ज़्यादातर की जा रही आलोचनाएं पुराने फ्रेमवर्क की कमियों को बताती हैं और फिर उन कमियों का कारण खुद सुधारों को बताती हैं। विकसित भारतङ्करोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम रोज़गार गारंटी को खत्म नहीं करता है बल्कि यह इसे और मजबूत और व्यापक बनाता है। खासकर उन कमज़ोरियों पर ध्यान देता है जहाँ ज़्यादा ज़रूरत वाले इलाकों और कमज़ोर मज़दूरों के बीच योजना के प्रभाव को सीमित कर दिया था। यहाँ सुधार का अर्थ सामाजिक सुरक्षा से पीछे हटना नहीं है; बल्कि यह काम के वादे को वास्तविक, भरोसेमंद और गरिमापूर्ण बनाने का एक प्रयास है।

(लेखक भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग में सचिव हैं)

मादुरो पर अमेरिकी हमले का फेंटानिल एंगल

पुष्परंजन

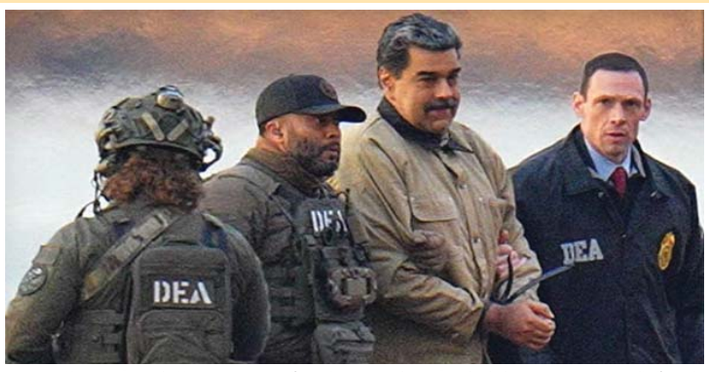

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर अमेरिका में नशीले कारोबार का सूत्रधार होने का आरोप लगाते रहे हैं, जिसके मूल में अमेरिकी युवाओं की रगों में जहर घोलने वाले उच्च तीव्रता के फेंटानिल की तस्करी शामिल रही है। कुछ जानकार बताते हैं कि फेंटानिल ही अमेरिकी हमले और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को फर्स्ट लेडी समेत हिरासत में लेने की सबसे बड़ी वजह रही है। जबकि वेनेजुएला के प्राकृतिक संसाधनों पर अमेरिकी लिप्सा किसी से?छिपी नहीं है।

दरअसल, फेंटानिल, धीरे-धीरे दुनियाभर में सुर्खियों में नजर आ रहा है। अटलांटिक के इस पार यह दवा उतनी प्रचलित नहीं है, लेकिन अमेरिका के अनुभवों को देखते हुए यह स्थिति बदलने वाली है। फेंटानिल एक ऐसी समस्या है, जो शायद ही कभी हल होगी। यह ड्रग, हेरोइन से सौ गुना अधिक घातक है। इसके लिए गांजे या अफ़ीम की खेती की ज़रूरत नहीं है। लैब में तैयार फेन्टानिल, एक शक्तिशाली दर्द निवारक दवा है, जो मॉर्फ्फिन से 50 गुना अधिक असरदार है। इसे मूल रूप से बेल्जियम के रसायनज्ञ पॉल जैन्सन द्वारा संश्लेषित किया गया था। इस दवा का उपयोग बड़ी सर्जरी के लिए होता रहा है, या फिर कैंसर से होने वाले असहनीय दर्द को कम करने में फेंटानिल उपयोगी है।

भले ही रासायनिक रूप से इसका अफ़ीम से कोई संबंध न हो, मगर यह दवा मॉर्फ्फिन और हेरोइन के समान ओपिओइड रिसेप्टर्स के साथ रिएक्ट करती है, इसलिए इसे 'ओपिओइड' कहा जाता है। हमारे शरीर में ऐसे रसायन निकलते हैं, जो हमें अच्छा महसूस कराते हैं, ये उन गतिविधियों को बूस्ट करते हैं, जैसे खान-पान का स्वाद लेने, या फिर यौन व्यवहार में। शरीर में अच्छा महसूस कराने वाले रसायनों की मात्रा बढ़ने के कारण ही ओपिओइड की लत लोग लगा लेते हैं। मतलब, दर्द निवारण के लिए निर्मित फेंटानिल, मौज-मस्ती का साधन बन चुका है। गंभीर चुनौती यह है कि फेंटानिल की लत एक बार लग गई तो उससे छुटकारा मौत के बाद ही मिल पाता है। साल 1960 के दशक से ही फेंटानिल के मूल तत्व में कई बदलाव और सुधार किए गए हैं, जिससे इसके अनेक प्रकार के वेरिएंट तैयार हुए हैं, जिनका शरीर पर अलग-अलग प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए, 'कार्फेंटानिल', मॉर्फ्फिन से हजारों गुना अधिक शक्तिशाली है।'कार्फेंटानिल' का उपयोग, उन्मत हाथियों को शांत करने के लिए किया जाता है।

हेरोइन और कोकीन जैसी दवाओं के साथ फेंटानिल को मिलाने से इसकी शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। केवल दो मिलीग्राम फेंटानिल एक वयस्क के लिए घातक हो सकता है। फेंटानिल अमेरिका के ओपिओइड संकट का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। सही से देखा जाये, तो हाल ही में यह खबर आई कि पिछले आठ महीनों में ब्रिटेन में फेंटानिल के कारण कम से कम 75 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन, अमेरिका में इस दवा के कारण मरने वालों की संख्या के मुकाबले यह कुछ भी नहीं है। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीसी) के अनुसार, '2024 में ड्रग ओवरडोज़ से 1,07,543 अमेरिकियों की मौत हुई, जिसमें फेंटेनाइल की वजह से 76,000 से ज़्यादा मौतें हुईं। 2025 तक अमेरिका में ड्रग ओवरडोज़ से होने वाली मौतों की दर दोगुनी से ज़्यादा हो गई, इसका बड़ा कारण फेंटानिल की सप्लाई में बढ़ोतरी थी।' डेटा एनालिसिस से पता चलता है, कि फेंटानिल की तस्करी में शामिल लोगों में 75 फीसद अमेरिकंस, करप्ट सिस्टम और पुलिस की सांठगांठ से लगे हुए हैं। ड्रग तस्करी में मात्र 25 प्रतिशत प्रवासी संलग्न दिखे। अर्थात?, अपने ही घर में ट्रम्प प्रशासन इसे रोक पाने में नाकारा साबित हुआ है।

ब्लूमबर्ग के अनुसार, 'ट्रम्प परिवार की नेट वर्थ लगभग 7.7 बिलियन डॉलर से घटकर 6.7 बिलियन डॉलर हो गई, जो डिजिटल एसेट्स में गिरावट से जुड़ी है।' कुछ रणनीतिकारों में माना है, कि फेंटानिल प्रोडक्शन से जुड़े क्रिप्टोकरेंसी-आधारित लेन-देन ने 'ट्रंप मेमेकॉइन' का भट्ठा बैठाया है। ट्रम्प केवल खिसियानी बिल्ली नहीं हुए, बल्कि उन्होंने सीधा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर झपट्टा मारा। लेकिन क्या, इससे फेंटानिल की तस्करी रुक जाएगी?

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

'एक धड़कन, जिसने ज़िंदगी बदल दी' : प्रोजेक्ट धड़कन के तहत ईलाज से मिली अरमान को हृदय रोग से मुक्ति

धनंजय राठौर, संयुक्त संचालक श्रुति सिंह, उप संचालक, जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़

रायपुर। गांव में मितानिन ने एक दिन कहा था, आपके बच्चे की धड़कन बाकी बच्चों से तेज है, यह वाक्य आज भी रजनी यादव के कानों में गूंजता है। वे बोलते-बोलते रो पड़ती हैं, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया अब लगता है, क्यों नहीं दिया!

गोगांव, रायपुर की रहने वाली रजनी यादव का तीसरा बेटा अरमान, अपने दोनों बड़े भाईयों और दोस्तों के साथ हंसता-खेलता बड़ा हो रहा था। कभी पिट्ठुल खेलता, कभी दौड़ लगाता, सब कुछ सामान्य लगता था। बस बार-बार होने वाला सर्दी-बुखार माता- पिता को थोड़ा परेशान जरूर करता था, लेकिन किसी को अंदेशा नहीं था कि उस मासूम सी हंसी के पीछे एक गंभीर खतरा छिपा है। फिर 13 दिसंबर 2025 का दिन आया। सरोरा स्थित शासकीय स्कूल में, कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशानुसार पहुँची चिरायु टीम ने जब बच्चों की जांच शुरू की, तो अरमान की बारी पर डॉक्टर ठिठक गए। उसके हृदय की धड़कन सामान्य नहीं थी। यही वह पल था, जिसने एक परिवार की ज़िंदगी की दिशा बदल दी।

प्रोजेक्ट धड़कन छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की एक स्वास्थ्य पहल है, जिसका उद्देश्य मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर बच्चों में जन्मजात हृदय रोगों (Congenital Heart Diseases - CHDs) का जल्द पता लगाना और उनका मुफ्त इलाज कराना है, जिसमें श्री सत्य साई हॉस्पिटल और जिला प्रशासन मिलकर काम कर रहे हैं, विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाकर बच्चों की जांच की जाती है और उन्हें आवश्यक डिजिटल उपकरण (जैसे स्टेथोस्कोप) प्रदान किए जाते हैं। टीम अरमान को तत्काल श्री सत्य साईं नारायण अस्पताल, नया रायपुर लेकर गई। विस्तृत जांच हुई और रिपोर्ट ने माता-पिता के पैरों तले ज़मीन खिसका दी। अरमान के दिल में 18 मिमी का छेद था। डॉक्टरों ने बिना देर किए कहा, ऑपरेशन जरूरी है। ईंट-भट्ठे में काम करने वाले पिता श्री रंगनाथ यादव और मां रजनी के सामने सवालों का पहाड़ खड़ा था कि पैसे का इंतजाम कैसे होगा? बच्चा का स्वास्थ्य, उसका भविष्य कैसा होगा? लेकिन उस घड़ी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। चिरायु टीम की सलाह पर भरोसा किया और अपने बेटे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। ज़िला प्रशासन द्वारा संचालित प्रोजेक्ट 'धड़कन' के अंतर्गत 28 दिसंबर 2025 को विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में अरमान का जटिल हृदय ऑपरेशन पूरी तरह नि:शुल्क सफ्लतापूर्वक किया गया। लगातार निगरानी और देखभाल के बाद कुछ ही दिनों में वह डिस्चार्ज होकर घर वापिस आ गया।

आज जब अरमान पिट्ठुल खेलता है, दोस्तों के पीछे भागता है, तो यह विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि सिर्फएक हफ्ते पहले वह अस्पताल में एक जटिल सर्जरी प्रक्रिया से गुजर रहा था। चिरायु टीम द्वारा लगातार फॉलो-अप किया जा रहा है। डॉक्टरों के अनुसार अरमान की सेहत में उल्लेखनीय सुधार है और वह पूरी तरह स्वस्थ है। उसके चेहरे की मुस्कान आज सिर्फ उसके परिवार की नहीं, पूरे मोहल्ले की खुशी बन गई है।

भावुक होकर श्रीमती रजनी यादव कहती हैं, अगर समय पर जांच और ईलाज नहीं मिलता, तो शायद आज मेरा बच्चा मेरे सामने न होता। वहीं पिता श्री रंगनाथ यादव कहते हैं, ष्मेरे पास न पैसा था, न साधन3 लेकिन प्रोजेक्ट धड़कन ने मेरे बेटे को नई ज़िंदगी दे दी। आज अरमान केवल अपने माता-पिता का सहारा नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए आशा, विश्वास और समय पर मिली मदद की ताकत का प्रतीक बन चुका है। रजनी और रंगनाथ, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ज़िला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते नहीं थकते।

यह कहानी सिर्फएक बच्चे के बचने की नहीं है - यह कहानी है संवेदनशील शासन, समय पर हस्तक्षेप और उस भरोसे की, जो एक मासूम दिल को फिर से धड़कने का मौका दे सका।

सशक्त मानसिकता से आत्मनिर्भरता की ओरः पोषण निर्माण में अहम भूमिका निभा रही हैं सूरजपुर की महिलाएं

सूरजपुर। आर्थिक सशक्तिकरण की नींव सशक्त मानसिकता पर आधारित होती है। दृढ़ इच्छाशक्ति, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास व्यक्ति को सफ्लता की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। सूरजपुर जिले की स्व-सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने इस सोच को व्यवहार में उतारते हुए आत्मनिर्भरता की एक सशक्त मिसाल प्रस्तुत की है। ये महिलाएं न केवल स्वयं सशक्त बन रही हैं, बल्कि जिले की महिलाओं एवं बच्चों को पोषण उपलब्ध कराने के अभियान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं एवं बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पोषण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तत्काल उपभोग हेतु तैयार पोषण आहार (रेडी टू ईट) निर्माण संयंत्र का शुभारंभ किया गया है। इन संयंत्रों में स्वादिष्ट एवं पौष्टिक नमकीन दलिया तथा मीठा शक्ति आहार का निर्माण किया जा रहा है, जो विटामिन 'ए', विटामिन 'डी', थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पाइरीडॉक्सिन, फोलिक अम्ल, कोबालामिन, लोह तत्व (आयरन), कैल्शियम एवं जिंक जैसे आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर है।

जिले प्रशासन द्वारा जिले में कुल 07 पोषण आहार निर्माण संयंत्र स्थापित किए गए है। यहां वर्तमान में भैयाथान, प्रतापपुर एवं सूरजपुर विकासखंड में तीन संयंत्रों का सफ्लतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। इन तीनों संयंत्रों में 32 महिलाएं प्रत्यक्ष रूप से पोषण आहार निर्माण कार्य में संलग्न हैं। निर्मित पोषण आहार आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को नि:शुल्क प्रदान किया जा रहा है। इस प्रकार स्व-सहायता समूहों की महिलाएं मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुदृढ़ीकरण में अप्रत्यक्ष किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बात है कि पोषण आहार के निर्माण के साथ-साथ उसके वितरण की भी जिम्मेदारी भी महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपी गई है। भैयाथान विकासखंड में 15 स्व-सहायता समूह,सूरजपुर विकासखंड में 15 स्व-सहायता समूह तथा प्रतापपुर विकासखंड में 13 स्व-सहायता समूह सक्रिय रूप से वितरण कार्य में अपनी भूमिका निभा रही है। इन समूहों के माध्यम से कुल 430 महिलाएं आंगनबाड़ी केंद्रों तक पोषण आहार वितरण कार्य में सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। इस योजना से महिलाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं।

ITR फाइल 500/-
Whatsapp पर बनवाएँ
Income Tax फाइल, GST रजिस्ट्रेशन, TDS रिफंड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट
CMA DATA, MSME, BALANCE SHEET, फूड लाइसेंस
हमारे Tax Expert आपकी मदद हेतु तैयार है।
www.onlytds.com
सम्पर्क - शेखर गुप्ता 9300755544 - 8878655544

श्रीकंचनपथ
भिलाई-दुर्ग

प्रिंट और डीजिटल मीडिया में
सभी प्रकार के विज्ञापन
के लिए
संपर्क करे
Mob.-:
9303289950
7987166110

प्रमुख खबरें

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेला 12 को

दुर्ग। आदर्श शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जी.ई. रोड पावरहाउस भिलाई में 12 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेला (पीएमएनएएम) का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला विभिन्न प्रतिष्ठित उद्योगों एवं कंपनियों में अप्रेंटिसशिप के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस मेले में 10वीं, 12वीं एवं आईटीआई उत्तीर्ण इच्छुक अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। अभ्यर्थियों को अपनी मार्कशीट, प्रमाण पत्र, रिज्यूम, आधार कार्ड सहित सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लाने के लिए कहा गया है। इसमें वासलोह बीके कास्टिंग, आत्मनिर्भर रेसिडेंशियल कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, विष्णु केमिकल लिमिटेड, सिम्प्लेक्स कास्टिंग्स, जय बालाजी इंडस्ट्रीस लिमिटेड, माइंडलैब्ज मीडिया टेक प्राइवेट लिमिटेड में अप्रेंटिसशिप के लिए योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी उपस्थित हो सकते हैं।

प्लेसमेंट कैम्प 13 जनवरी को, 337 पदों पर होगी भर्ती

दुर्ग। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र में 13 जनवरी 2026 को प्रात: 10:30 बजे से प्लेसमेंट केम्प का आयोजन किया जाएगा। इस प्लेसमेंट कैम्प में निजी क्षेत्र के तीन नियोजकों से प्राप्त रिलेशनशिप मैनेजर-12 पद, इलेक्ट्रीशियन-200 पद, फील्ड ऑफिसर-25 पद, असिस्टेंट मैनेजर ट्रेनी-20 पद, डिप्टी एडवाइजर-20 पद, सेल्स ऑफिसर-20 पद, कलेक्शन ऑफिसर-20 पद और रिलेशनशिप ऑफिसर- 20 पद कुल 337 रिक्त पदों हेतु भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। उक्त सभी पदों हेतु वेतन 15000 से 40000 रूपये तक है। साथ में 10वी, 12वी, आईटीआई, डिप्लोमा एवं कोई भी स्नातक शैक्षणिक योग्यता धारी आवेदक उक्त प्लेसमेंट कैम्प में सम्मिलित हो सकतें है। विस्तृत जानकारी दृहश्द्ध-gar.cg.gov.in, chhattisgarh rozgar app अथवा रोजगार कार्यालय के सूचना पटल के माध्यम से प्राप्त कर सकते है।

स्टेशन रोड गुरुद्वारा में श्रद्धा से मनाया प्रकाश पर्व

दुर्ग। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का पावन प्रकाश पर्व 5 जनवरी को गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, स्टेशन रोड, दुर्ग में विशेष गुरमत समागम का आयोजन किया गया। इस पावन समागम में स्त्री सत्संग सभा, दुर्ग, हम चाकर गोबिंद के संस्था सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्य एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया।

नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने समन्वय बैठक

दुर्ग। आगामी नेशनल लोक अदालत तथा 'मध्यस्थता राष्ट्र के लिए 2.0' अभियान को सफलता बनाने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्ग के विश्राम कक्ष में एक समन्वयात्मक बैठक आयोजित की गई।

नियमों का उल्लंघन करने पर औद्योगिक इकाइयों को तत्काल बंद करवाने के निर्देश

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। जिले में पर्यावरण नियमों की अनदेखी करने वाले औद्योगिक संस्थानों पर जिला प्रशासन ने सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। कलेक्टर जनदर्शन में प्राप्त शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए कलेक्टर अभिजित सिंह के निर्देशन में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने जिले की विभिन्न इकाइयों का औचक निरीक्षण किया। जांच में गंभीर अनियमितताएं और प्रदूषण पाए जाने पर क्षेत्रीय कार्यालय, भिलाई द्वारा संबंधित इकाइयों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी किया गया है।

यह कार्रवाई मुख्य रूप से भिलाई-03 तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में की गई है। जिसके अंतर्गत ग्राम अकलौरडीह-जरवाय, ग्राम जरवाय तथा कुम्हारी क्षेत्र शामिल है। ग्राम अकलौरडीह-जरवाय में संचालित

मेसर्स आर.डी. एजेंसी (वेस्ट मटेरियल स्क्रीनिंग यूनिट) को भारी धूल और बिना अनुमति संचालन के कारण बंद करने का आदेश दिया गया है। ग्राम जरवाय स्थित मेसर्स पंकज अग्रवाल (स्लैग क्रशिंग यूनिट) और मेसर्स टेथिस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड पर भी नियमों के उल्लंघन के चलते कार्रवाई की गई है। तथा कुम्हारी क्षेत्र अहिवारा रोड स्थित मेसर्स वैद्य फूड प्रोडक्ट्स में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण न होने के कारण उसे भी बंद करने के आदेश दिए गए हैं। पर्यावरण मंडल ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई विधिक प्रावधानों के अंतर्गत की गई है। जिसमें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' शामिल है। संबंधित उद्योगों को अपनी गतिविधियां तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए है।

मकर संक्रांति पर 'हमारे सपनों का आंगन' का होगा आयोजन, तैयारियों में जुटा चेम्बर

लक्ष्य : महिला व्यापारियों का उत्साहवर्धन, होगी उपहारों की भी बारिश

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की महिला चेम्बर द्वारा आगामी 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति के पावन अवसर पर 'हमारे सपनों का आंगन' को सफल बनाने एवं महिला व्यापारियों का उत्साहवर्धन करने के लिए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन आज चेम्बर भवन में महिला विंग की अध्यक्ष डॉ. इला गुप्ता एवं वरिष्ठ पदाधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ।

मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में 'म्यूजिकल तंबोला' और 'पाक कला प्रतियोगिता' का विशेष आकर्षण रहेगा। यह आयोजन छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी एवं महिला चेम्बर अध्यक्ष डॉ. इला गुप्ता के कुशल नेतृत्व में दोपहर 3.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक आयोजित किया जाएगा।

कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए महिला चेम्बर महामंत्री मनीषा तारवानी, कोषाध्यक्ष नम्रता अग्रवाल और कोऑर्डिनेटर स्वाति सोनी को प्रोग्राम डायरेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, चेम्बर के सांस्कृतिक प्रभारी अनिल जोतसिंघानी कार्यक्रम के संयोजक की भूमिका निभाएंगे।

पोस्टर विमोचन के अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी, कोषाध्यक्ष निकेश बरडिया, संरक्षक एवं महिला चेम्बर विंग प्रभारी तिलोक चंद बरड़िया, कार्यकारी अध्यक्ष राजेश वासवानी, उपाध्यक्ष दिलीप इसरानी सहित महिला चेम्बर पदाधिकारी संरक्षक श्रीमती मीनाक्षी टूटेजा, कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती मधुबाला सिंह, और सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। महिला चेम्बर ने शहर की महिलाओं से इस उत्सव में उत्साहपूर्वक भाग लेने की अपील की है।

भाग लेने के लिए इनसे करें संपर्क
डॉ. ईला गुप्ता
प्रदेश अध्यक्ष-महिला चेम्बर
मो. 92001-26862
मनीषा तारवानी
प्रदेश महामंत्री-महिला चेम्बर
मो. 94255-02398
नम्रता अग्रवाल
प्रदेश कोषाध्यक्ष-महिला चेम्बर
मो.9827822285

सोना-चांदी समेत बम्पर पुरस्कार

प्रतिभागियों के लिए शानदार पुरस्कार रखे गए हैं:- प्रथम- माइक्रोवेव ओवन, द्वितीय- सोने की अंगूठी, तृतीय पुरस्कार- स्मार्ट मोबाइल फोन। इसके अतिरिक्त, विजेताओं को बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के और अन्य ढेरों उपहार प्रदान किए जाएंगे।

सर्व ब्राह्मण मित्र सखी का मंगट्टा में मिलन समारोह

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। मंगट्टा स्थित लिलीपुट रिसोर्ट में सर्व ब्राह्मण मित्र सखी की लगभग 50 सखियों ने नववर्ष 2026 का मिलन समारोह बड़े उत्साह, उल्लास और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया। सामाजिक मेलजोल बढ़ाने में ऐसे आयोजनों की अच्छी भूमिका होती है।

कार्यक्रम की शुरुआत सभी सखियों द्वारा पहाड़ी माता मंदिर एवं काली माता मंदिर में पूजन एवं दर्शन के साथ की गई। माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त करने के उपरांत विप्र नारी शक्ति द्वारा नववर्ष में किए जाने वाले सामाजिक, सांस्कृतिक एवं संगठनात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई।

इसके पश्चात सखियों ने भजन, मनोरंजक खेलों एवं आपसी संवाद के माध्यम से कार्यक्रम को अत्यंत उत्साहपूर्वक मनाया। पूरे आयोजन में आपसी एकता, सहयोग और सकारात्मक ऊर्जा का सुंदर दृश्य देखने को मिला।

सरोज चौबे, उर्मिला उपाध्याय, पूनम मिश्रा, कामिनी तिवारी, मृदुला शुक्ला, अंजू त्रिपाठी, अनीता पर्वत, सुधा शर्मा सहित अन्य सखियाँ रहीं।

कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी विप्र सखियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सखियों के इस आयोजन ने न केवल नववर्ष के स्वागत को सार्थक बनाया, बल्कि समाज में नारी शक्ति, एकता और संस्कारों को भी सुदृढ़ करने का संदेश दिया।

प्रभारी मंत्री की अनुशंसा पर दो विस क्षेत्रों के लिए 57.30 लाख के विकास कार्य स्वीकृत

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जिले के दो प्रमुख विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 57.30 लाख रूपए से अधिक की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा द्वारा अनुशंसित इन कार्यों के लिए वर्ष 2025-26 के आबंटन से राशि जारी की गई है।

इस स्वीकृति के तहत दुर्ग शहर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु 29.97 लाख रूपए और दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में विकास हेतु 27.33 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। इन कार्यों के संपादन के लिए क्रमश: ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग-दुर्ग और जनपद पंचायत दुर्ग को क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार दुर्ग शहर विधानसभा के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 40 में स्थित सामुदायिक भवन में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य हेतु 9.99 लाख की स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 40 में ही सामुदायिक भवन में रसोई कक्ष एवं शौचालय निर्माण कार्य के लिए 5.00 लाख स्वीकृत किए गए हैं। वार्ड क्रमांक 56 बघेरा के मोहलई रोड के समीप सामुदायिक भवन निर्माण कार्य के लिए 9.99 लाख तथा सामुदायिक भवन में शौचालय निर्माण कार्य हेतु 4.99 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी क्रम में दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के अंतर्गत ग्राम थनौद के सतनाम पारा में और ग्राम कोकडी के निषाद पारा में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य के लिए 10-10 लाख की स्वीकृति दी गई है। ग्राम भानपुरी के वार्ड 02 में सार्वजनिक भवन के पास किचन शेड निर्माण कार्य हेतु 3.40 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही, ग्राम एवं ग्राम पंचायत अछोटी के भाठापारा क्षेत्र की विभिन्न गलियों में नाली निर्माण कार्य के लिए 3.93 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

सत्यानंद योग प्रतियोगिता में दुर्ग जिला बना चैम्पियन

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। छत्तीसगढ़ प्रेम निरंजन योगासन खेल संघ एवं योग लंगर समिति भिलाई के तत्वाधान में परमहंस स्वामी सत्यानंद जी की स्मृति में आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता का सफल आयोजन सम्पन्न हुआ। प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्ग के लगभग 150 प्रतिभागियों ने भाग लिया। दो दिवसीय प्रतियोगिता में टीम चैंपियनशिप का खिताब दुर्ग जिले ने अपने नाम किया, जबकि राजनांदगांव जिला उपविजेता रहा एवं सक्ती जिले को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ।

विभिन्न आयु वर्गों में विजेता प्रतिभागी क्रमश: इस प्रकार रहे - बालक वर्ग (5 से 9 वर्ष - आर्टिस्टिक योग): प्रथम तनय, श्रेयांश, द्वितीय तनिष्क, रविकांत एवं तृतीय दिलेश्वर, गुरवेंद्र। बालक (9 से 14): प्रथम शिवांश, केतन, द्वितीय नितेश, अविनाश, तृतीय रामेश्वरम, सुबोध।

बालिका वर्ग प्रथम अंतरा, निशिका, द्वितीय कुलदीपिका, दीक्षका, तृतीय याचना, सैनी। बालिका वर्ग (14 से 19 वर्ष): प्रथम आयुष, प्रियांशी, द्वितीय हर्षिता, नयना, (19 से 28 वर्ष): प्रथम प्रियंका, रामिशा।

प्रतिभागियों ने ट्रेडिशनल योगासन, आर्टिस्टिक योगा (सिंगल व पेयर) तथा रिदमिक योगा जैसे विभिन्न इवेंट्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

समापन अवसर पर भिलाई इस्पात संयंत्र ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र बंछोर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अध्यक्षता नगर निगम रिसाली के सभापति केशव बंछोर ने की। मुख्य अतिथि नरेंद्र बंछोर ने योग के माध्यम से स्वास्थ्य एवं कल्याण के प्रति प्रतिभागियों की प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए कहा कि योग जीवन को संतुलित और अनुशासित बनाता है। वहीं अध्यक्षीय उद्बोधन में केशव बंछोर ने कहा कि योग न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक एवं नैतिक विकास का भी सशक्त माध्यम है। समापन समारोह में विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी, प्रमाण पत्र एवं पदक प्रदान कर सम्मानित किया गया।

मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान

मतदाता सूचि में नाम जोड़ने गर्ल्स कालेज में शिविर

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। शासकीय डॉ वावा पाटणकर कन्या स्नानकोत्तर महाविद्यालय मे 5 जनवरी को छात्राओं हेतु मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु स्थानीय प्रशासन के सौजन्य से महाविद्यालय के 'स्वीप समिति' एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में शिविर का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. रंजना श्रीवास्तव ने कहा कि मतदान केवल संवैधानिक अधिकार ही नहीं अपितु प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्त्तव्य है। देश के प्रत्येक मतदाता को मतदान करना ही चाहिए, जिससे लोकतंत्र मजबूत होगा।

अत: 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी प्रत्येक छात्रा को मतदाता सूची में अपना नाम अनिवार्यत: जुड़वाना चाहिए।

इस अवसर पर महाविद्यालय की छात्राओं ने नुक्कड़-नाटक का मंचन भी किया। जिसके माध्यम से छात्राओं ने समस्त महाविद्यालयीन छात्राओं का आह्वान किया कि लोकतंत्र के मजबूत गठन हेतु मतदाता सूची में नाम जुड़वाना एवं मतदान कितना महत्वपूर्ण है। इस हेतु नाटक के माध्यम से छात्राओं को जागरूक किया गया। इस आयोजन में लगभग 65 छात्राओं नें मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु आवेदन (प्रारूप-6) जमा किया ।

इस अवसर पर वार्ड क्रमांक-225 भाग क्रमांक-225 के बी.एल.ओ. महावीर ध्रुव, डॉ. अमिता सहगल, स्वीप प्रभारी डॉ. विजय कुमार वासनिक, राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रभारी डॉ. यशेश्वरी ध्रुव एवं डॉ. सुषमा यादव एवं महाविद्यालय के प्राध्यापकगण तथा छात्रायें बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

कार्यक्रम का संचालन 'स्वीप समिति' के संयोजक डॉ. विजय कुमार वासनिक ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉ. मिलिन्द अमृतफले ने किया।

अंतर इस्पात संयंत्र वॉलीबॉल प्रतियोगिता चयन स्पर्धा 15 से

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। एलॉय इस्पात संयंत्र द्वारा एसपीएसबी अंतर इस्पात संयंत्र वालीबॉल प्रतियोगिता 2025-26 का आयोजन एएसपी स्टेडियम, ए-जोन, स्टील टाउनशिप में दिनांक 15 से 17 जनवरी 2026 तक किया जा रहा है।

इस प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु भिलाई इस्पात संयंत्र (बी.एस.पी.) की टीम का चयन क्रीड़ा, सांस्कृतिक एवं नागरिक सुविधाएँ विभाग द्वारा की जा रही चयन स्पर्धा के माध्यम से किया जाएगा। इस चयन स्पर्धा का आयोजन 08 जनवरी 2026 को संध्या 06:30 बजे से भिलाई इस्पात संयंत्र के वालीबॉल ग्राउंड, पंत स्टेडियम, सेक्टर-1 में किया जाएगा।

भिलाई इस्पात संयंत्र के कार्मिक, उनके परिवारजन और भिलाई परिधीय क्षेत्र के बेरोजगार युवा खिलाड़ी इस चयन स्पर्धा में भाग ले सकते हैं।

इन नंबरों पर करें संपर्क

चयन स्पर्धा में भाग लेने के इच्छुक खिलाड़ी अपना पंजीकरण 08 जनवरी 2026 को संध्या 06:00 बजे तक चयनकर्ता दीपक मित्रा (मो. नं: 9407986416), अजय कुमार सोनी (मो. नं: 9407985785) एवं ख्वाजा अहमद (मो. नं: 9406427865) के पास करवा सकते हैं। इस चयन स्पर्धा के प्रभारी उप प्रबंधक (की.सा. एवं ना.सु.) अभिजीत भौमिक होंगे।

Since 1972
CROWN® TV
Choice Of Millions
Washing Machine / Cooler
Available All Size

CONTACT :
Atlas Radio Traders (Crown)
Sect.-3, D-48, Ward No. 22
Devendra Nagar, Raipur (C.G.) 492009
Near Akash Gas Agency Line

खास खबर

प्लास्टिक प्रोसेसिंग इकाई के संचालन हेतु 16 जनवरी तक आवेदन आमंत्रित

सूरजपुर। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत जिले के 06 विकासखंड के 04 ग्राम पंचायत में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रोसेसिंग इकाई स्थापित किया गया है। उक्त प्लास्टिक अपशिष्ट इकाई (पीडब्लूएमयू) के संचालन कार्य के लिए इच्छुक रिसाईक्लर्स, फर्म या थर्ड पार्टी से मोहर बंद लिफाफे में आवेदन (रूचि की अभिव्यक्ति) 16 जनवरी दोपहर 12 बजे तक आमंत्रित किया गया है। अधिक जानकारी के लिए जिला पंचायत सूरजपुर के सूचना पटल एवं जिले के वेबसाइट पर अवलोकन कर सकते हैं।

रबी फसल के लिए कोडार एवं केशवा जलाशय से छोड़ा गया पानी

महासमुंद। किसानों की मांग और आवश्यकताओं को देखते हुए गत दिवस कोडार जलाशय से रबी फसल के लिए खेतों में पानी देने पर निर्णय लिया गया। महासमुंद विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा की पहल पर 5 जनवरी से ही खेतों में पानी दिए जाने का निर्णय लिया गया था, जिस पर आज अमल किया गया। जिले के कोडार जलाशय परियोजना वृहद परियोजना अंतर्गत पानी छोड़ा गया। कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला जल उपयोगिता समिति विनय कुमार लंगेह ने जल संसाधन के मुख्य कार्यपालन अभियंता अजय कुमार खरे को पानी छोड़ने का निर्देश दिया। रबी सिंचाई के लिए कोडार वृहद परियोजना में बांयी तट नहर प्रणाली से 13 गांवों के 1600 हेक्टेयर क्षेत्र का रकबा सिंचाई सुविधा के लिए प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा केशवा नाला जलाशय से भी पानी छोड़ा गया है।

घोड़ारी में अस्पृश्यता निवारणार्थ सद्भावना शिविर 30 को

महासमुंद। अनुसूचित जातियों के हित में शासन द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आदिवासी विकास विभाग द्वारा अस्पृश्यता निवारणार्थ एवं प्रचार-प्रसार सद्भावना शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शिल्पा साय ने बताया कि यह शिविर 30 जनवरी 2026 को महासमुंद विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम घोड़ारी में प्रात: 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगा। शिविर में जिले के विभिन्न विभागों द्वारा सहभागिता करते हुए अपने-अपने विभागीय योजनाओं, सुविधाओं एवं लाभों की विस्तृत जानकारी आम नागरिकों को प्रदान की जाएगी।

रोशनी महिला संकुल की 18 दीदियों को मिले असील नस्ल के चूजे

जगदलपुर। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी रोशनी महिला संकुल संगठन माड़पाल के अंतर्गत एकीकृत कृषि क्लस्टर योजना के तहत संचालित इस ब्रूडिंग सेंटर से सोमवार को तीसरे बैच के चूजों का विधिवत विक्रय किया गया। इस अवसर पर विशेष रूप से 'असील' नस्ल के चूजों का वितरण किया गया, जो स्थानीय जलवायु के अनुकूल होने के साथ-साथ अपनी बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं। इस पहल के तहत कुल 18 दीदियों को चूजे प्रदान किए गए, जिससे वे अपने घर से ही मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू कर सकेंगी। इससे न केवल उनकी पारिवारिक आय में वृद्धि होगी, बल्कि गांव स्तर पर आजीविका के नए अवसर भी सृजित होंगे। यह योजना ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने में प्रभावी भूमिका निभा रही है।

महासमुंद जिले को मिली तीन मेडिकल यूनिट वाहन

महासमुंद। प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत महासमुंद जिले को 3 मोबाइल मेडिकल यूनिट वाहनों की सौगात मिली है। यह मोबाइल मेडिकल यूनिट महासमुंद, बागबाहरा एवं पिथौरा विकासखंडों के 75 से अधिक गाँवों में भ्रमण कर विशेष रूप से पीवीटीजी कमार जनजाति के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराएँगी। मुख्य रूप से धनसूली, पाटनदादर, अमेठी, जोरातराई, रैताल, धरमपुर, गुलझर गाँवों में जाएंगी।

विकास पर चर्चा : सुकमा के 75 ग्राम-पंचायतों के सदस्यों से मिले उपमुख्यमंत्री शर्मा

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रशिक्षण प्राप्त करने आये सुकमा जिले के 75 ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों के दल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने गांवों के पंचायत प्रतिनिधियों से उनके ग्रामों के विकास पर विस्तृत चर्चा की। इस दल में सुकमा जिले के ग्राम सरपंच, उपसरपंच, पंच शामिल थे। सभी ने उपमुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बात रखी। सभी से मुलाकात कर उन्होंने उनके ग्रामों की समस्याओं को जाना।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने सभी से चर्चा में वनोपज के संग्रहण एवं विपणन के संबंध में जानकारी ली। जिसपर ग्राम पंचायत जनप्रतिनिधियों ने बताया कि वे स्थानीय बिचौलियों को अपने वनोपज का विक्रय करते हैं, जिसपर उपमुख्यमंत्री ने उन्हें वनोपज का ग्राम के युवाओं द्वारा संग्रहण करा कर शासन के माध्यम से बड़े बाजारों तक पहुंचाते हुए अपने वनोत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया।

उन्होंने वनोपजों के स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण कराकर उनका मूल्यवर्धन करने की सलाह दी। इसके लिए सभी ग्रामों के 10-10 लोगों को हैदराबाद जैसे बड़े बाजारों में शैक्षणिक भ्रमण कराकर उन्हें प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के लाभों से अवगत कराने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया।

उन्होंने सभी पंचायत जनप्रतिनिधियों से गांवों में शांति बहाल होने के साथ ही विकास के तीव्र गति से चलाने और इलवद पंचायत योजना का लाभ लेने को प्रेरित किया। जनप्रतिनिधियों ने भी अपने ग्रामों की समस्याओं को उनके समक्ष रखा जिस पर उपमुख्यमंत्री ने उन्हें जल्द से जल्द निराकरण हेतु आश्वश्त किया। उन्होंने ग्रामों में बिहान योजना, बैंकिंग सुविधा, सड़क, बस्तर ओलंपिक, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधा पर विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर पंचायत विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह भी उपस्थित थीं।

बाल विवाह रोकने नदी-नाला फांदकर 'नाड़ीगुफा' गांव पहुंची बचाव की टोली

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा संचालित बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से साकार होता नजर आ रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग एवं जिला प्रशासन की सतर्कता और संवेदनशीलता के चलते दुर्गम एवं पहुँचविहीन क्षेत्र में नदी-नाले पार कर 12 वर्षीय बालिका का बाल विवाह समय रहते रोका गया। इस त्वरित कार्रवाई से न केवल एक मासूम का भविष्य सुरक्षित हुआ, बल्कि बाल विवाह जैसी कुप्रथा के विरुद्ध सशक्त संदेश भी गया।

2 जनवरी को प्रशासन को सूचना मिली थी कि सुकमा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत रामाराम के सुदूर गांव नाड़ीगुफा में एक नाबालिक बालिका का विवाह किया जा रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर के मार्गदर्शन में तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसके पश्चात जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के नेतृत्व में जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड लाइन तथा विभागीय अमले की संयुक्त टीम गठित की गई। टीम ने उफनते नदी-नालों और अत्यंत दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद पैदल यात्रा कर गांव तक पहुँच बनाई और समय रहते विवाह प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया।

मौके पर यह पाया गया कि पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह की सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी थीं। अधिकारियों द्वारा परिजनों एवं ग्रामीणों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों, कानूनी दायित्वों तथा इसके गंभीर सामाजिक दुष्परिणामों की जानकारी दी गई। प्रशासन की समझाइश का सकारात्मक प्रभाव पड़ा और परिजनों ने स्वेच्छा से बाल विवाह रोकने का निर्णय लिया। ग्रामीणों की उपस्थिति में विधिवत पंचनामा तैयार कर कार्रवाई को औपचारिक रूप दिया गया।

कार्रवाई के दौरान बालिका को पुन: शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने तथा उसके सुरक्षित सम्मानजनक भविष्य के लिए परिजनों को प्रेरित किया गया। साथ ही शासन की विभिन्न बाल संरक्षण एवं शिक्षा से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी गई।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा 10 मार्च 2024 को बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का शुभारंभ किया गया था। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा 13,823 बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों को अधिसूचित किया गया है। अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप नवंबर 2025 तक प्रदेश में 189 बाल विवाह रोके जा चुके हैं। बालोद जिला पूर्णत: बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया जा चुका है, जो पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणास्रोत है। वर्ष 2025-26 के लिए राज्य शासन ने 31 मार्च 2026 तक राज्य की 50 प्रतिशत ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त घोषित करने तथा 31 मार्च 2029 तक छत्तीसगढ़ को पूर्णत: बाल विवाह मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने स्पष्ट किया है कि बच्चों का सुरक्षित, शिक्षित एवं गरिमामय भविष्य सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं के उन्मूलन हेतु सतर्कता, जनजागरूकता एवं कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

जनहितैषी स्वीकृत कार्यों को समय सीमा में पूरा किया जाए

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। आदिम जाति विकास मंत्री तथा मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम ने आज अपने एक दिवसीय जिला प्रवास के दौरान कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शासन की प्राथमिकता एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल विशेष रूप से उपस्थित थे।

प्रभारी मंत्री श्री नेताम ने बैठक में कहा कि पुराने बजट में स्वीकृत सभी लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समय-सीमा में पूर्ण किया जाए, किसी भी प्रकार की ढिलाई या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने आजीविका मिशन, मखाना उत्पादन, मत्स्य पालन और कृषि से जुड़े विषयों पर जिले की परिस्थितियों के अनुरूप ठोस और व्यावहारिक रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए।

मंत्री श्री नेताम ने कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि इस जिले की जलवायु नकदी फसलों के लिए अत्यंत अनुकूल है। उन्होंने किसानों को पारंपरिक खेती के साथ-साथ उद्यानिकी, दलहन-तिलहन, सब्जी एवं अन्य नकदी फसलों की ओर प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। मखाना की खेती को जिले के लिए संभावनाशील बताते हुए इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ करने तथा कृषि विभाग एवं कृषि विज्ञान केंद्र को संयुक्त रूप से तिल एवं अरहर की खेती के लिए वैज्ञानिक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। मंत्री श्री नेताम ने पशुधन विकास एवं मत्स्य पालन विभाग की समीक्षा में कुक्कुट पालन, बकरी पालन, सूकर पालन और मत्स्य पालन को ग्रामीण आय बढ़ाने का प्रभावी माध्यम बताया और अधिक से अधिक किसानों को प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता से जोड़ने पर बल दिया।

अम्बेडकर अस्पताल में टीएचआर और टीकेआर सर्जरी का मिलने लगा लाभ

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर के ऑर्थोपेडिक विभाग में अब टोटल हिप रिप्लेसमेंट (टीएचआर) एवं टोटल नी रिप्लेसमेंट (टीकेआर) जैसी अत्याधुनिक सर्जिकल सुविधाएं पूर्व की भाँति सुचारु रूप से मरीजों के लिए उपलब्ध हैं। अस्थि रोग विभाग की इस सुविधा से कूल्हे एवं घुटने की गंभीर समस्याओं से जूझ रहे मरीजों को बड़ी राहत मिल रही है।

अस्थि रोग विभागाध्यक्ष डॉ. आर. के. दास के अनुसार, गठिया, ऑस्टियो-आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, दुर्घटना या लम्बे समय से जोड़ों के दर्द से पीड़ित मरीजों के लिए यह सर्जरी अत्यंत लाभकारी साबित हो रही है। सर्जरी के पश्चात मरीज सामान्य जीवन की ओर तेजी से लौट पा रहे हैं।

उन्होंने मरीजों से अपील की है कि हिप (कूल्हे) या नी (घुटने) की पुरानी समस्या को नजरअंदाज न करें और समय पर ऑर्थोपेडिक विभाग की ओपीडी में परामर्श लेकर उपचार कराएं।

अम्बेडकर अस्पताल के अधीक्षक डॉ. संतोष सोनकर ने कहा कि अम्बेडकर अस्पताल में टोटल हिप रिप्लेसमेंट एवं टोटल नी रिप्लेसमेंट की सुविधा पूर्व की भाँति पूरी तरह उपलब्ध है। अत्याधुनिक तकनीक, मानक प्रोटोकॉल एवं अनुभवी चिकित्सकों की टीम द्वारा यह सर्जरी सुरक्षित रूप से की जा रही है। विगत कुछ दिनों में करीब 8 मरीजों की जोड़ प्रत्यारोपण सर्जरी की जा चुकी है।

इन सर्जरी के माध्यम से मरीजों को लम्बे समय से चले आ रहे असहनीय दर्द से स्थायी राहत मिलती है तथा उनके जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होता है। शासकीय अस्पताल में यह सुविधा उपलब्ध होने से मरीजों को आयुष्मान योजना के द्वारा निशुल्क उच्चस्तरीय इलाज मिल रहा है।

राज्य बाल संरक्षण नीति पर परामर्श कार्यशाला

यूनिसेफ के सहयोग से सार्थक रही चर्चा, सभी संबंधितों की रही उपस्थिति

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बच्चों के संरक्षण, अधिकारों की सुरक्षा और उनके सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण नीति-2025 के ड्राफ्ट प्रारूप को अंतिम रूप देने हेतु राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से आयोजित यह कार्यशाला एक सुदृढ़, समन्वित एवं अधिकार-आधारित बाल संरक्षण तंत्र विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम रही।

कार्यशाला में नीति के मसौदे पर विशेषज्ञों, हितधारकों एवं विभागीय अधिकारियों से अंतिम सुझाव प्राप्त किए गए। इस दौरान बाल विवाह एवं बाल श्रम की रोकथाम, अनाथ व बेसहारा बच्चों का पुनर्वास, बाल तस्करी, हिंसा, उपेक्षा, कुपोषण तथा साइबर अपराधों से बच्चों की सुरक्षा जैसे विषयों पर गहन विमर्श हुआ।

महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी ने नीति के ड्राफ्ट एवं कार्ययोजना की प्रस्तुति देते हुए बताया कि यह नीति किशोर न्याय अधिनियम, 2015, ह्यष्टऋष्ट एवं अन्य राष्ट्रीय विधिक प्रावधानों के अनुरूप, राज्य की सामाजिक व भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जा रही है।कार्यशाला में छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने बाल अधिकारों की निगरानी, शिकायत निवारण तंत्र को सशक्त करने तथा संस्थागत एवं गैर-संस्थागत देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर बल दिया।

इस अवसर पर संयुक्त सचिव स्कूल शिक्षा फरिहा आलम, संचालक समाज कल्याण रोक्तिमा यादव, संचालक ट्रेजरी और एकाउंट पद्मिनी भोई साहू, संचालक महिला एवं बाल विकास डॉ. रेणुका श्रीवास्तव, यूनिसेफ की प्रतिनिधि चेतना देसाई, कर्नाटक राज्य के प्रतिनिधि, संयुक्त संचालक नन्दलाल चौधरी, उप संचालक नीलम देवांगन सहित स्वास्थ्य, गृह (पुलिस), श्रम, पंचायत एवं नगरीय प्रशासन विभागों के अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थाएं एवं कानूनी विशेषज्ञ उपस्थित रहे।

तकनीकी सत्र में अर्लेन मनोहरन, सोनी कुट्टी जॉर्ज, एम.आर. गोविंद बेनीवाल, निमिषा श्रीवास्तव, नूपुर पांडे, चिरंजीवी जैन, प्रमोद गुप्ता एवं प्रभात कुमार ने नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, बहु-विभागीय समन्वय और निगरानी व्यवस्था पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। ड्राफ्ट नीति की समीक्षा हेतु प्रतिभागियों को विभिन्न समूहों में विभाजित कर गहन चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि प्राप्त सुझावों को सम्मिलित कर छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण नीति-2025 को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिससे यह राज्य के प्रत्येक बच्चे के लिए सुरक्षा और अधिकारों का मजबूत कवच बन सके।

वन मंत्री ने पुसपाल में दी 11.18 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने कोंडागांव जिले के मर्दापाल तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत पुसपाल मे 11 करोड़ 18 लाख 21 हजार रुपये लागत के 10 विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। यह सभी कार्य क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण और जनसुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी। श्री कश्यप ने शिक्षा विभाग द्वारा स्कूली विद्यार्थियों को सरस्वती साइकिल योजना के तहत 85 विद्यार्थियों को साइकिल वितरण किया।

मंत्री केदार कश्यप ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता अंतिम व्यक्ति तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं, साथ ही आदिवासी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बस्तर पंडूम का उल्लेख करते हुए कहा कि यह आयोजन आदिवासी कला, संस्कृति और परंपराओं को पुनर्जीवित रखने का सशक्त माध्यम है। हमारी परंपराएं बचेंगी तो हमारी पहचान और प्रकृति भी सुरक्षित रहेगी, उन्होंने बस्तर पंडूम में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी की अपील भी की। मंत्री श्री कश्यप ने एसआईआर के द्वितीय चरण की जानकारी देते हुए कहा कि यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची से छूटने न पाए।

ग्राम पंचायत पुसपाल में स्टॉप डेम निर्माण के लिए 249.94 लाख रुपये, ग्राम खड़पड़ी में उप स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण के लिए 34.00 लाख रुपये, वहीं मर्दापाल मुख्य मार्ग से आदावल तक 5.50 किमी डामरीकरण सड़क निर्माण कार्य के लिए 305.38 लाख रुपये के कार्य शामिल हैं। इसी प्रकार पोहार से चेराकुड़ तक 6 किमी डामरीकरण सड़क निर्माण के लिए 264.34 लाख रुपये, ग्राम रेंगागोंदी में नाले पर स्टॉप डेम सह पुलिया निर्माण के लिए 249.55 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमिपूजन और राज्य कैम्पा वन विभाग अंतर्गत कोरमेल, जोंडेंगा, कोंगेरा, तोडेम एवं मड़गांव ग्राम पंचायतों में देव वनों के संरक्षण-संवर्धन हेतु 05 देवगुड़ी निर्माण के लिए प्रत्येक कार्य हेतु 3.00 लाख रुपए स्वीकृत कार्य शामिल है।

इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग द्वारा स्कूली विद्यार्थियों को सरस्वती साइकिल योजना के तहत हासेल 6, मटवाल 11, हसालनार 39 एवं बयारनार 29 विद्यार्थियों को साइकिल वितरण किया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य श्रीमती यशोदा कश्यप, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अनिता कोर्राम ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।

गिधौरी की उचित मूल्य दुकान संचालन समिति निलंबित

कोरबा। ग्राम पंचायत गिधौरी, विकासखंड करतला, जिला कोरबा स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकान (आई.डी. क्रमांक 552002038), जिसका संचालन चन्द्राकर खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्यादित गिधौरी द्वारा किया जा रहा था, के विरुद्ध गंभीर अनियमितताएँ पाए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा कठोर कार्रवाई की गई है। वार्षिक सत्यापन वर्ष 2025 के दौरान संचालक संस्था द्वारा पीडीएस संचालन कार्य में उल्लेखनीय अनियमितताएँ सामने आईं। स्टॉक परीक्षण में चावल के स्टॉक में 143.71 क्विंटल तथा नमक के स्टॉक में 13.47 क्विंटल की कमी परिलक्षित हुई। संचालक संस्था का यह आचरण छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की विभिन्न कंडिकाओं तथा निष्पादित अनुबंध पत्र में उल्लिखित प्रमुख शर्तों का सीधा उल्लंघन है। इस मामले में पंजीबद्ध प्रकरण पर संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, जिसका जवाब निर्धारित समय-सीमा के भीतर नहीं मिला।

गंजेपन से मुक्ति मात्र 1 घंटे में
COMPLETE FAMILY SALON
हेयर रिप्लेसमेंट, 100% संतुष्टि की गारंटी
पहले बाद में
JITU'Z
CUT N SHINE
93009-11331
रंगोली बेंगल्स के सामने, जयसवाल इलेक्ट्रानिक के बाजू में इंदिरा मार्केट, स्टेशन रोड, दुर्ग (छ.ग.)

GST NO. 22AHMPB9621P1Z2
PH.: 0788-4060131
अनुप ट्रेडर्स
आर्टिफिशियल ज्वेलरी के विक्रेता
लिंक रोड, केम्प-2, पावर हाउस, भिलाई
मो. 09826389666, 8839749539

राहुल मोदी से अफेयर की चर्चाओं के बीच श्रद्धा कपूर ने शादी की योजना पर दी प्रतिक्रिया, बोलीं- मैं विवाह करूंगी

श्रद्धा कपूर बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा और जबरदस्त फैन फॉलोइंग वाली एक्ट्रेस मानी जाती हैं। यही नहीं वो इंडस्ट्री की मोस्ट डिजायरेबल बैचलर्स एक्ट्रेस में से भी एक हैं। राहुल मोदी के साथ कथित रिलेशनशिप की खबरों के बाद फैंस उनकी शादी का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब आखिर श्रद्धा ने एक फैन को जवाब देते हुए अपनी शादी पर चुप्पी तोड़ी है और शादी पर बात की है। जानिए श्रद्धा ने अपनी शादी को लेकर क्या कुछ कहा और फैन को ऐसा क्या जवाब दिया, जो अब वायरल है।

श्रद्धा कपूर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने ज्वेलरी ब्रांड का एक प्रमोशनल वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में अभिनेत्री यह बताती नजर आ रही हैं कि आंकड़े बताते हैं कि ज्यादातर ब्रेकअप वैलेंटाइन डे के आसपास होते हैं। फिर वह इसके पीछे के संभावित कारणों पर विचार करती हैं और शरारती अंदाज में कहती हैं कि लोग प्यार के इस मौसम में अकेले रहने से बचने के लिए उनके गिफ्ट बॉक्स खरीद सकते हैं। अपने वीडियो के कैप्शन में भी श्रद्धा ने फैंस से यही पूछा है, 'किस किसका ब्रेकअप वैलेंटाइन के करीब हुआ है?'

श्रद्धा बोलीं- मैं विवाह करूंगी

श्रद्धा कपूर के इस वीडियो पर कई लोगों ने अभिनेत्री से उनकी शादी को लेकर सवाल कर डाला। तो कुछ ने तो उन्हें अपना वैलेंटाइन बनने के लिए ही पूछ लिया। इसी क्रम में एक यूजर ने उनकी शादी की योजना को लेकर सवाल करते हुए, कमेंट में लिखा, 'श्रद्धा जी आप शादी कब करोगे?' ये कमेंट वायरल तब हो गया, जब श्रद्धा ने इस पर रिप्लाई करते हुए अपना जवाब दिया। एक्ट्रेस ने बिना झिझक जवाब देते हुए लिखा, 'मैं करूंगी, विवाह करूंगी।' श्रद्धा का ये जवाब अब सोशल मीडिया पर वायरल है और उनके जल्द ही शादी करने की खबरों को भी बल दे रहा है।

राहुल मोदी के साथ जुड़ रहा श्रद्धा का नाम

श्रद्धा कपूर का नाम पिछले कुछ वक्त से राहुल मोदी के साथ जोड़ा जा रहा है। दोनों को कई मौकों पर साथ भी देखा गया है। हालांकि, दोनों में से किसी ने भी अपने रिश्ते पर कभी कुछ नहीं बोला। श्रद्धा और राहुल के बीच डेटिंग की अफवाहें सबसे पहले 2024 की शुरुआत में मुंबई में डिनर डेट के बाद एक साथ देखे जाने से उठीं। श्रद्धा कभी-कभी इंस्टाग्राम पर उनकी मजेदार तस्वीरें पोस्ट करती रहती हैं। उनके अलग होने की अफवाहें भी उड़ी थीं, लेकिन श्रद्धा ने दिसंबर 2024 में इंस्टाग्राम पर राहुल के साथ वड़ा पाव डेट की एक तस्वीर पोस्ट करके इन अफवाहों को खारिज कर दिया। वर्कफ्रंट की बात करें तो श्रद्धा कपूर आखिरी बार 'स्त्री 2' में नजर आई थीं। वहीं श्रद्धा के आगामी प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इनमें 'ईथा', जो प्रसिद्ध मराठी लोक कलाकार विथाबाई नारायणगांवकर के जीवन पर आधारित एक बायोपिक ड्रामा है। इसके अलावा 'नागिन' और 'स्त्री 3' में भी श्रद्धा के होने की चर्चाएं हैं।

लंबे समय बाद सेट पर लौटीं कंगना रनौत, शुरू की भारत भाग्य विधाता की शूटिंग

बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी से सांसद कंगना रनौत काफी समय से फिल्मों से दूर और राजनीति में ज्यादा सक्रिय हैं। अभिनेत्री ने शीतकालीन सत्र में कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा था, लेकिन अब काफी समय बाद कंगना वापस फिल्मी सेट पर लौटी हैं। उन्होंने शूटिंग करते हुए वीडियो पोस्ट किया है। सेट पर वापसी करने का अनुभव अभिनेत्री के लिए खुश कर देने वाला है।

कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह मनोज तापड़िया के साथ दिख रही हैं। अभिनेत्री सेट पर बाकी लोगों के साथ मिलजुल रही हैं और मनोज तापड़िया उन्हें फिल्म के सीन भी समझा रहे हैं। उन्होंने वीडियो को शेयर कर लिखा, फिल्म के सेट पर वापसी कर अच्छा लग रहा है। कंगना फिल्म इमरजेंसी के बाद लंबे समय के बाद दूसरी फिल्म की शूटिंग कर रही हैं, जिसका नाम है भारत भाग्य विधाता। इमरजेंसी के रिलीज के साथ कंगना ने भारत भाग्य विधाता की अनाउंसमेंट कर दी थी, लेकिन अब तकरीबन एक साल बाद फिल्म की शूटिंग शुरू की गई है। भारत भाग्य विधाता को यूनोइया फिल्म्स की बबीता आशिवाल और फ्लोटिंग रॉक्स एंटरटेनमेंट के आदि शर्मा मिलकर प्रोड्यूस करने वाले हैं, जबकि डायरेक्ट मनोज तापड़िया करेंगे, जिन्होंने मद्रास कैफे, चीनी कम, एनएच10, और माई जैसी फिल्मों को डायरेक्ट किया है। भारत भाग्य विधाता एक देशभक्ति फिल्म है, जिसमें उन महान वीरों की कहानियों को दिखाया जाएगा, जिनके बारे में कम ही लोगों को पता है। फिल्म की कहानी वीरता और साहस की भावना से भरी होने वाली है, लेकिन फिल्म कब रिलीज होगी, इस बारे में जानकारी सामने नहीं आई है।

बता दें कि अभिनेत्री की आखिरी रिलीज फिल्म इमरजेंसी सिनेमाघरों में फ्लॉप साबित हुई थी। फिल्म के रिलीज पर भी बैन लगा दिया गया था, लेकिन कुछ बदलावों के साथ फिल्म को रिलीज की अनुमति मिल गई। इमरजेंसी का निर्माण और निर्देशन दोनों ही कंगना ने किया था। इसके अलावा, फिल्म में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रोल भी प्ले किया था। इस फिल्म के लिए कंगना ने खूब मेहनत की थी, लेकिन फिर भी फिल्म पर्दे पर कमाल नहीं दिखा पाई थी।

यश की फिल्म टॉक्सिक ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन अप्स में 'मेलिसा' के रूप में रुक्मिणी वसंत का अनावरण

यश की टॉक्सिक ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स हर नए खुलासे के साथ और भी गहरी, डार्क और बेबाक होती जा रही है। यह फिल्म अब एक ऐसी सिनेमाई दुनिया गढ़ रही है, जो हर मोड़ पर चौंकाती है। इसी रोमांचक सफर में मेकर्स ने एक बड़ा पत्ता खोला है—रुक्मिणी वसंत की एंट्री, जो 'मेलिसा' के किरदार में नजर आएंगी। शालीन, प्रभावशाली और बिल्कुल न झुकने वाली मेलिसा के रूप में रुक्मिणी की मौजूदगी फिल्म के इंटेंस ड्रामा को एक नया आयाम देती है। यह फिल्म रुक्मिणी वसंत और यश के बीच पहली दमदार साझेदारी को भी चिन्हित करती है, वो भी निर्देशक गीतू मोहनदास की खास सिनेमाई दृष्टि के साथ।

अपनी समझदार परफॉर्मेंस और भावनात्मक गहराई के लिए जानी जाने वाली रुक्मिणी की एंट्री इस बात का संकेत है कि दर्शकों को एक ऐसी अदाकारी देखने को मिलेगी, जो गीतू की परतदार और माहौल रचने वाली कहानी कहने की शैली में पूरी तरह घुली-मिली होगी। वहीं यश का सपना भी साफ झलकता है—एक ऐसी भारतीय फिल्म बनाना, जो स्केल में ग्लोबल हो और भावनाओं में हर किसी से जुड़ जाए। नादिया के रूप में कियारा आडवाणी, एलिज़ाबेथ के रूप में हुमा कुरैशी, गंगा के रूप में नयनतारा और रेबेका के रूप में तारा सुतारिया के दमदार फर्स्ट लुक्स के बाद, अब टॉक्सिक की रहस्यमयी दुनिया में मेलिसा की एंट्री होती है। 1960 के दशक के आखिरी दौर की एक रंगीन लेकिन धुंधली पार्टी की पृष्ठभूमि में मेलिसा खुद को पूरे आत्मविश्वास के साथ पेश करती हैं। चारों ओर जश्न, शोर और हलचल है, लेकिन उनकी नजरें एकदम सटीक और दृढ़ हैं। जहां बाकी दुनिया बहती हुई सी लगती है, वहीं मेलिसा हर कदम सोच-समझकर रखती हैं, ऐसे अंदाज़ में कि पूरी महफिल पर उनका ही असर छा जाता है।

हर नए खुलासे के साथ फिल्म और भी धारदार होती जा रही है। इसका भावनात्मक दायरा फैल रहा है, सिनेमाई पैमाना और बड़ा हो रहा है और टॉक्सिक खुद को 2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित भारतीय फिल्मों में मजबूती से स्थापित कर रही है।

निर्देशक गीतू मोहनदास कहती हैं, रुक्मिणी में मुझे सबसे ज्यादा जो चीज़ पसंद है, वो है एक कलाकार के तौर पर उनकी बुद्धिमत्ता। वो सिर्फ अभिनय नहीं करतीं, वो किरदार को समझती हैं, उसे प्रोसेस करती हैं। उनके सवाल शक से नहीं, जिज्ञासा से आते हैं और यही बात मुझे भी एक निर्देशक के तौर पर और गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। कई बार तो अपने ही फैसलों पर दोबारा विचार करने लगती हूं। उन्हें काम करते देख मुझे एहसास होता है कि स्क्रीन पर इंटेलिजेंस अक्सर वहां होती है, जो कहा नहीं जाता। शूट के बीच-बीच में मैं उन्हें चुपचाप अपनी डायरी में कुछ लिखते देखती हूं—सेट से जुड़े छोटे किस्से, अपने विचार। ये छोटे पल उनके प्रोसेस के बारे में बहुत कुछ कह जाते हैं। वो लगातार अपनी एक अंदरूनी दुनिया बना रही होती हैं। उनका यह अप्रोच मुझे बेहद सोच-समझ से भरा लगता है और सच कहूं तो कई बार मन करता है कि उनकी डायरी के पन्ने चुपके से पढ़ लूं, ताकि उस दिमाग को समझ सकूं, जो इतनी परतदार परफॉर्मेंस के पीछे है। यश और गीतू मोहनदास द्वारा लिखी गई और गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी टॉक्सिक- ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स को कन्नड़ और अंग्रेज़ी में एक साथ फिल्माया गया है। इसके साथ ही हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कई अन्य भाषाओं में डब वर्ज़न की योजना है, जो इसके ग्लोबल विज़न को साफ दर्शाता है।

राहु केतु का ट्रेलर रिलीज, बड़े पर्दे पर अब मचेगा कॉस्मिक कॉमेडी का बवाल

ज़ी स्टूडियोज़ और ब्लाइव प्रोडक्शन्स के बैनर तले बनी फिल्म राहु केतु का बहुप्रतीक्षित ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और आते ही इसने साफ कर दिया है कि दर्शकों को मिलने वाला है एक ऐसा पागलपन भरा सफर, जहां पौराणिक कथाएं टकराएंगी आज के हंगामे से और हंसी के पीछे छुपा होगा एक बड़ा कॉस्मिक मैसेज। चुटीले ह्यूमर, शार्प राइटिंग और दमदार परफॉर्मेंस से भरा यह ट्रेलर एक ऐसी फिल्म का वादा करता है, जो जितनी एंटरटेनिंग है, उतनी ही सोचने पर मजबूर करने वाली भी। ट्रेलर की शुरुआत होती है पियूष मिश्रा की प्रभावशाली आवाज़ से, जो अपनी खास कहानी कहने की शैली में राहु और केतु के पौराणिक महत्व से दर्शकों को रूबरू कराते हैं।

फिल्म की कमान संभालते हैं पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा, जिनकी कॉमिक टाइमिंग और आपसी केमिस्ट्री ट्रेलर में ही दिल जीत लेती है। पुलकित अपने किरदार में चार्म, चालाकी और अनिश्चितता लेकर आते हैं, जो शॉर्टकट और महत्वाकांक्षा से चलने वाला है। वहीं वरुण शर्मा एक बार फिर साबित करते हैं कि सिचुएशनल कॉमेडी उनका मजबूत हथियार है, जहां उनका फिज़िकल ह्यूमर और ऑब्ज़र्वेशनल कॉमिक सेंस खूब रंग जमाता है। फिल्म की थीम पर बात करते हुए पुलकित सम्राट कहते हैं, फैंटेसी की दुनिया हमेशा से मुझे आकर्षित करती रही है। राहु केतु में जो बात मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगी, वो था इस रंगीन और अराजक यूनिवर्स का हिस्सा बनना, जो पूरी तरह कॉमेडी से जुड़ा है।

पौराणिक विचारों को मज़ेदार और आसान अंदाज़ में, खासकर बच्चों के लिए, ज़िंदा होते देखना और उस सफर का हिस्सा बनना मेरे लिए बेहद खुशी की बात रही। वहीं वरुण शर्मा जोड़ते हैं, राहु केतु का ह्यूमर पूरी तरह सिचुएशंस और इंसानी कमज़ोरियों से निकला है। हम सिर्फ लोगों को हंसा नहीं रहे, बल्कि एक आईना दिखा रहे हैं, बस थोड़ा सा पागलपन, ढेर सारी मस्ती और अराजकता के साथ। शालिनी पांडे ट्रेलर में एक मजबूत और आत्मविश्वासी अवतार में नज़र आती हैं। उनका किरदार कहानी को भावनात्मक गहराई देता है और फिल्म की नैतिक रीढ़ को मज़बूती से थामे रखता है, जिससे स्क्रीन पर चल रहे पूरे हंगामे को एक ठोस दिशा मिलती है।

अपने किरदार के बारे में बात करते हुए शालिनी पांडे कहती हैं, राहु केतु मेरे करियर के सबसे मज़ेदार सफरों में से एक रहा है। विपुल विग का विज़न बहुत स्पष्ट है, लेकिन वह अपने कलाकारों को अपनी सहज प्रवृत्ति लाने की पूरी आज़ादी देते हैं, जिससे काम करने का अनुभव बेहद खास बन जाता है। अपने को-एक्टर्स के साथ काम करना शानदार रहा और ज़ी स्टूडियोज़ व ब्लाइव प्रोडक्शन्स ने जिस भरोसे और जुनून के साथ फिल्म को सपोर्ट किया है, वह स्क्रीन पर साफ झलकता है। मैं दर्शकों के रिएक्शन का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूं। सपोर्टिंग कास्ट भी ट्रेलर की जान है।

चंकी पांडे अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग के साथ एक और यादगार परफॉर्मेंस देते हैं, वहीं अमित सियल अपनी संयमित और गहरी अदायगी से फिल्म के हाई एनर्जी पागलपन को ज़मीन पर टिकाए रखते हैं। राहु केतु को सबसे अलग बनाता है खुद राहु और केतु का पौराणिक रूप में आगमन, जो कहानी को एक बड़े दार्शनिक स्तर पर ले जाता है। उनकी मौजूदगी फिल्म के मूल संदेश को मजबूती देती है।

मुंबई के प्रदूषण से हिना खान की सेहत पर पड़ा बुरा असर सांस लेने में हो रही तकलीफ

भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई हमेशा अपने तेज रफ्तार जीवन और चमक-दमक के लिए जानी जाती है। हाल के वर्षों में मुंबई में हवा की गुणवत्ता लगातार गिरती जा रही है और लोगों के लिए दिन-प्रतिदिन की जिंदगी मुश्किल बनती जा रही है। प्रदूषण ने ना सिर्फ आम लोगों की सेहत पर असर डाला है, बल्कि सेलिब्रिटी भी इससे अछूते नहीं हैं।

टीवी की लोकप्रिय अभिनेत्री हिना खान ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि वह बढ़ते प्रदूषण की समस्या से परेशान हैं और इससे उनके स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है। हिना खान ने कहा, मुंबई की बिगड़ती हवा के कारण मुझे सांस लेने में मुश्किल हो रही है। प्रदूषण की वजह से लगातार खांसी है और यह सेहत पर बुरा असर डाल रहा है। ब्रेस्ट कैंसर से जूझने के कारण यह मेरे लिए और भी चुनौतीपूर्ण है।

खास खबर

खरीदी केंद्रों से नियमित धान उठाव पर हो फोकस - कलेक्टर

कवर्धा। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय सीमा की बैठक लेकर विभागीय कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने विभागों के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों की बारी बारी समीक्षा करते हुए कहा कि सभी स्वीकृत निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिए जाएं, काम प्रारंभ होना लंबित न हो। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से उनके विभाग के अंतर्गत चल रहे कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग कर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत टंकी निर्माण और पाइप लाइन बिछाने के पूर्ण हो चुके स्थानों में विद्युत कनेक्शन और पंप इंस्टॉलेशन के लंबित कार्यों के बारे जानकारी ली और कहा कि जल्द सभी कार्य पूर्णता वाले स्थलों में कनेक्शन और इंस्टॉलेशन का कार्य पूर्ण कर लिया जाए। कलेक्टर वर्मा ने पीएम आवास और जनमन के तहत स्वीकृत आवास निर्माण के बारे में सीईओ जनपदों से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सभी कार्यों जल्द पूरा करें। इसके लिए उन्होंने विभागीय अधिकारियों को नियमित फील्ड निरीक्षण हेतु निर्देशित किया। कलेक्टर श्री वर्मा ने बैठक में पीएम सूर्यघर के तहत सोलर पैनल इंस्टॉलेशन की गति बढ़ाते हुए योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में आगामी गणतंत्र दिवस के गरिमामयी आयोजन के लिए शासन के निर्देशानुसार विभागीय अधिकारियों को सभी तैयारियां करने के लिए निर्देशित किया गया। राज्य शासन द्वारा जिला मुख्यालय के साथ ब्लॉक, तहसील एवं नगरीय निकायों में आयोजन के लिए प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप आयोजन समारोह का सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए।

सरगुजा ओलंपिक 2025-26 : आदिवासी अंचल की खेल प्रतिभाओं को मिलेगा नया मंच

सूरजपुर। सरगुजा संभाग, जो कि अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, खेल प्रतिभाओं से परिपूर्ण माना जाता है। यहां के युवाओं में खेलों के प्रति स्वाभाविक रुचि और अपार क्षमता को पहचानकर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सरगुजा ओलंपिक 2025-26 का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मंशानुरूप तथा खेल मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री (खेल एवं युवा कल्याण विभाग) अरुण साव के मार्गदर्शन में आयोजित यह प्रतियोगिता आदिवासी अंचल के युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगी। सरगुजा ओलंपिक 2025-26 निश्चित रूप से क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध होगा।इस आयोजन का उद्देश्य शासन और जनता के बीच मजबूत एवं प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करते हुए युवाओं की रचनात्मक और खेल प्रतिभा को निखारना है। सरगुजा ओलंपिक में कुल 12 खेलों की प्रतियोगिताएं विकासखण्ड, जिला एवं संभाग स्तर पर आयोजित की जाएंगी।पंजीयन अवधि: 28 दिसम्बर 2025 से 12 जनवरी 2026 तक,विकासखण्ड स्तरीय आयोजन: 15 जनवरी 2026 से 18 जनवरी 2026,जिला स्तरीय आयोजन: 22 जनवरी 2026 से 25 जनवरी 2026 और संभाग स्तरीय आयोजन: 28 जनवरी से 31 जनवरी 2026 (उक्त तिथियां खेल एवं युवा कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ की अनुमति के पश्चात परिवर्तनीय हो सकती हैं।) सरगुजा ओलंपिक हेतु ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पंजीयन की सुविधा प्रदान की गई है। ऑनलाइन पंजीयन लिंक 2025 के माध्यम से तथा ऑफ्लाइन पंजीयन कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाः स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिंचाई से किसानों को बहुआयामी लाभ

45 से 55 प्रतिशत तक मिल रहा अनुदान, चालू वित्तीय वर्ष में 19306 किसानों का 16154 हेक्टेयर कृषि रकबा सिंचित

- ड्रिप सिंचाई प्रणाली - सब्जी, फल, बागवानी एवं नकदी फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी
- अल्प वर्षा क्षेत्रों में यह योजना किसानों के लिए वरदान

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में कृषि उत्पादन एवं रकबा बढ़ाने हेतु निरंतर प्रयास किया जा रहा है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम के प्रयासों से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत राज्य के 19306 किसानों को स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिंचाई प्रणाली का लाभ दिलाते हुए उनके 16154 हेक्टेयर खेती भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाने हेतु किसानों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। इस योजना के तहत लघु सीमांत कृषकों को 55 प्रतिशत तथा दीर्घ किसानों के लिए 45 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान किया गया है। जिससे किसान कम लागत में आधुनिक सिंचाई तकनीक का लाभ उठा सकें।

छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के अधिकारियों ने बताया कि स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिंचाई प्रणाली के उपयोग से फसलों को आवश्यकतानुसार एवं सामान रूप से पानी उपलब्ध हो रहा है। इससे जल की 30 से 40 प्रतिशत तक बचत हो रही है। साथ ही खेतों में जल अपव्यय पर प्रभावी नियंत्रण संभव हुआ है। सीमित जल संसाधनों के बेहतर उपयोग से खेती अधिक लाभकारी बन रही है।

ड्रिप सिंचाई प्रणाली विशेष रूप से सब्जी, फल, बागवानी एवं नकदी फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रही है, जबकि स्प्रिंकलर प्रणाली से दलहन, तिलहन एवं अनाज फसलों की उत्पादकता में वृद्धि दर्ज की जा रही है। किसानों के अनुसार इन प्रणालियों के उपयोग से उपज में 20 से 30 प्रतिशत तक वृद्धि तथा उर्वरक एवं श्रम लागत में कमी आई है।

इस योजना के अंतर्गत किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, डिज़ाइन अनुमोदन एवं स्थापना में सहयोग भी प्रदान किया जा रहा है। इससे किसानों में आधुनिक तकनीकों के प्रति जागरूकता बढ़ी है और वे वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। सूखा एवं अल्प वर्षा प्रभावित क्षेत्रों में यह योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है।

कम पानी में अधिक उत्पादन होने से किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ हो रही है और उनकी आय में स्थायी वृद्धि हो रही है। वर्ष 2025-26 में अब तक स्प्रिंकलर के सेट 15 हजार 757 कृषकों के खेतों में 12 हजार 212 हेक्टेयर एवं ड्रिप सिस्टम के 3 हजार 549 कृषकों के खेतों में 3 हजार 942 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापना हुई।

शासन की योजना बनी सहारा : हेमचंद के परिवार को मिला प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के हर परिवार को सुरक्षित और पक्का आवास देने के विज़न के अनुरूप प्रधानमंत्री आवास योजना ज़मीनी स्तर पर लोगों की ज़िंदगी बदल रही है। इसी का जीवंत उदाहरण हैं नगर पंचायत फरसगांव, जिला कोंडागांव के वार्ड क्रमांक 4 निवासी हेमचंद नाग, जिन्होंने इस योजना के माध्यम से अपने पिता तिरकू राम नाग को पक्का मकान उपहार में दिया।

हेमचंद नाग ने बताया कि उनका पुराना मकान बांस और मिट्टी से बना हुआ था, जो बरसात के दिनों में बार-बार क्षतिग्रस्त हो जाता था। कमजोर दीवार के कारण परिवार के सभी सदस्यों पिता, पत्नी और दो बच्चों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। हालात ऐसे हो गए थे कि सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें अपने पिता को कुछ समय के लिए भाई के घर भेजना पड़ा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और पात्र हितग्राहियों तक लाभ पहुँचाने की नीति के तहत, वार्ड स्तर पर जानकारी के दौरान हेमचंद नाग को योजना से जोड़ा गया। नगर पंचायत एवं संबंधित अधिकारियों की सक्रिय भूमिका से आवास स्वीकृत हुआ और 29 वर्गमीटर क्षेत्रफल का पक्का मकान 3.05 लाख रुपये की लागत से बनकर तैयार हुआ।

गृह प्रवेश के शुभ अवसर पर हेमचंद नाग ने सबसे पहले अपने पिता के हाथों विधिवत पूजा करवाई और भावनाओं के साथ यह पक्का मकान उन्हें समर्पित किया। नया घर देखकर पिता भावुक हो उठे। हेमचंद नाग ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का विज़न केवल योजनाओं की घोषणा तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक सम्मान, सुरक्षा और आत्मविश्वास पहुँचाना है।

उन्होंने इस उपलब्धि के लिए पार्षद, मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं नगर पंचायत के समस्त कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री आवास योजना से बदली ममता की जिंदगी

श्रीकंचनपथ न्यूज

बिलासपुर। मंगला धूरीपारा की रहने वाली ममता कौशिक का जीवन कभी कठिनाइयों से भरा था। सीमित आय में घर चलाना और ऊपर से कच्चे मकान की परेशानियाँ, बरसात में टपकती छत, गर्मी में तपता कमरा और हर मौसम में असुरक्षा का एहसास। परिवार की आय इतनी नहीं थी कि वे पक्का मकान बनवा सकें। पक्का घर उनके लिए सिर्फ एक सपना था। यह सपना तब हकीकत में बदला जब उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का लाभ मिला। योजना के तहत मिली आर्थिक सहायता से उनका वर्षों पुराना सपना साकार हुआ। आज श्रीमती ममता कौशिक अपने पक्के घर में सुरक्षित, सम्मानजनक और सुकूनभरा जीवन जी रही हैं। जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का आभार जताया है।

ममता बताती हैं, पहले हर बरसात अपने साथ डर लेकर आती थी, कच्चे घर की मुश्किलें बारिश में और बढ़ जाती थी। पक्का घर बनने के बाद अब अपने घर की मजबूत छत के नीचे बच्चों और परिवार के साथ चौन की नींद सो पाती हूँ। यह सिर्फ घर नहीं, बल्कि मेरे जीवन की नई शुरुआत है। वे मानती हैं कि अगर यह योजना न होती तो पक्का घर बनवाना उनके परिवार के लिए असंभव ही रहता, और वे रोजाना कच्चे घर की मुश्किलों से जूझते रहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की यह पहल गरीब परिवारों को सम्मान की छत के साथ आत्मसम्मान और स्थिरता भी दे रही है।

कृषि महाविद्यालय के छात्र-छात्राएं कृषि विज्ञान केन्द्र में सीख रहे तकनीकी ज्ञान

श्रीकंचनपथ न्यूज

कवर्धा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के तहत संचालित कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र के चतुर्थ वर्ष के छात्र-छात्राओं को रेडीश्रावे कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि विज्ञान केन्द्र में 05 जनवरी 2026 से 07 जनवरी 2026 तक संलग्न किया गया है। कार्यक्रम के तहत छात्र-छात्राओं को उद्यानिकी, शस्य विज्ञान, कीट विज्ञान, रोग विज्ञान, वानिकी एवं कृषि अभियांत्रिकी के नई तकनीक एवं केन्द्र में संचालित अनुसंधान कार्यों की विस्तृत जानकारी दी जा रही है।

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. बी. पी. त्रिपाठी द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रमुख उद्देश्य एवं गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी गई तथा धान, दलहन, तिलहन एवं सब्जियों, फूलों के विभिन्न रोग, रोगकारक तथा उनके निदान के संबंध में छात्र-छात्राओं को बताया गया तथा कीट एवं रोग प्रबंधन के लिए किये जा रहे प्रक्षेत्र परीक्षण एवं अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन के बारे में अवगत कराया गया। विषय वस्तु विशेषज्ञ, उद्यानिकी, डॉ. एन. सी. बंजारा द्वारा फलदार पौधों में वानस्तिक प्रर्वधन विधि जैसे गुटी बांधना, कटिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग फलदार वृक्षों को रोग से बचाव के लिए बोर्डो पेस्ट बनाने की विधि, सब्जियों के बीज उत्पादन विधि, सब्जियों के नर्सरी बेड बनाने की विधि का जीवंत प्रदर्शन कराया गया तथा मशरूम उत्पादन की जानकारी दी गई।

सुशासन और पारदर्शिता की दिशा में रायगढ़ जिला प्रशासन की अभिनव पहल

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायगढ़। राज्य शासन की सुशासन, पारदर्शिता एवं जनहितकारी प्रशासन की अवधारणा के अनुरूप रायगढ़ जिला प्रशासन द्वारा भू-अर्जन प्रकरणों में मुआवजा भुगतान प्रक्रिया को सुगम, सरल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से एक अभिनव पहल की शुरुआत की गई है। जिला प्रशासन द्वारा यह नई व्यवस्था रायगढ़ अनुविभाग अंतर्गत 26 सितंबर 2025 से प्रभावशील की गई है।

इस पहल के तहत भू-अर्जन से प्रभावित किसानों को मुआवजा एवं पुनर्वास तथा बोनस की राशि सीधे ऑनलाइन बैंकिंग प्रक्रिया के माध्यम से उनके बैंक खातों में अंतरित की जा रही है। इससे भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होने के साथ-साथ किसानों को होने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों का भी समाधान हो रहा है।

जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 26 सितंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 की अवधि में भू-अर्जन मुआवजा मद अंतर्गत कुल 92 प्रभावित किसानों को 8 करोड़ 66 लाख 57 हजार 210 रूपए का भुगतान किया गया है। वहीं पुनर्वास एवं बोनस मद अंतर्गत 224 किसानों को 5 करोड़ 46 लाख 25 हजार 599 रुपए की राशि का वितरण किया गया है। इस प्रकार मुआवजा एवं पुनर्वास दोनों को मिलाकर कुल 316 किसानों को 14 करोड़ 12 लाख 82 हजार 809 रुपए की राशि सीधे उनके खातों में अंतरित की गई है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भू-अर्जन प्रकरणों में मुआवजा राशि का भुगतान चेक के माध्यम से किया जाता था, जिससे किसानों को चेक प्राप्त करने, बैंक में लंबी प्रक्रिया, भुगतान में विलंब तथा बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। नई ऑनलाइन व्यवस्था से यह सभी बाधाएं समाप्त हो गई हैं।किसानों को मिल रही हैं अनेक प्रत्यक्ष सुविधाएं इस अभिनव व्यवस्था से जिले प्रभावित किसानों को कई महत्वपूर्ण सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। अब उन्हें न तो चेक लेने के लिए कार्यालय जाना पड़ता है और न ही बैंक में अनावश्यक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। मुआवजा एवं पुनर्वास राशि सीधे खातों में जमा होने से किसानों के समय और धन दोनों की बचत हो रही है। साथ ही डिजिटल भुगतान से लेन-देन का स्पष्ट रिकॉर्ड उपलब्ध होने के कारण किसी भी प्रकार की त्रुटि या विवाद की संभावना भी न्यूनतम हो गई है। ऑनलाइन भुगतान प्रणाली से किसानों को बिना किसी मध्यस्थ के पारदर्शी तरीके से राशि प्राप्त हो रही है, जिससे उनमें शासन एवं जिला प्रशासन के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है। समय पर राशि मिलने से किसान अपनी कृषि एवं पारिवारिक आवश्यकताओं की योजना बेहतर ढंग से बना पा रहे हैं।

जल जीवन मिशन से ग्रामवासियों को मिल रही राहत, घर-घर पहुंच रहा शुद्ध पेयजल

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। जल जीवन मिशन आज गांवों के लिए बहुत बड़ी राहत बन गया है। इस योजना से अब ग्रामीण परिवारों को अपने घर में ही साफऔर सुरक्षित पीने का पानी मिलने लगा है। इससे वर्षों से चली आ रही पानी की समस्या से लोगों को स्थायी राहत मिली है। रोजाना शुद्ध पानी मिलने से ग्रामीणों का जीवन अब पहले से ज्यादा आसान और सुरक्षित हो गया है।

पहले गांवों में पानी के लिए लोगों को दूर-दूर तक जाना पड़ता था। खासकर महिलाओं को रोज कई किलोमीटर पैदल चलकर पानी लाना पड़ता था। इससे उनका समय, मेहनत और सेहत तीनों प्रभावित होते थे। पानी की कमी के कारण खाना बनाने, सफाई रखने और पशुओं की देखभाल जैसे कामों में भी काफी परेशानी होती थी। पानी हमारे जीवन की सबसे जरूरी जरूरत है।

सुबह से लेकर रात तक हर काम में पानी चाहिए। पानी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसी जरूरत को समझते हुए सरकार ने हर घर जल के लक्ष्य के साथ जल जीवन मिशन शुरू किया, ताकि गांव-गांव तक पीने का पानी पहुंचाया जा सके।

इसी योजना से लाभ पाने वाली कबीरधाम जिले के पंडरिया विकासखंड की ग्राम पंचायत खाम्ही के आश्रित ग्राम रोखनी की रहने वाली श्रीमती सुकली बाई बताती हैं कि उम्र बढ़ने के कारण उनके लिए दूर से पानी लाना बहुत मुश्किल हो गया था। नहाने, खाना बनाने और मवेशियों के लिए पानी जुटाना भी बड़ी समस्या थी। घर में पानी नहीं होने से रोजमर्रा के सभी काम प्रभावित होते थे। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत घर में नल कनेक्शन मिलने के बाद अब उन्हें पानी के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। घर में ही पर्याप्त मात्रा में साफ पानी मिल रहा है, जिससे उनका जीवन अब पहले से कहीं ज्यादा आसान और सुरक्षित हो गया है। श्रीमती सुकली बाई ने जल जीवन मिशन के माध्यम से घर तक शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। आज इस योजना के जरिए जिले के लाखों घरों में नल से पानी पहुंच रहा है। इससे लोगों की सेहत में सुधार हुआ है, समय की बचत हो रही है और जीवन स्तर भी बेहतर हुआ है। यह योजना गांवों के विकास की दिशा में एक बहुत ही सराहनीय कदम है।

स्वीकृत ले-आउट से विचलन पर वॉलफोर्ट एलेन्सिया परियोजना के प्रमोटर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने रायपुर स्थित वॉलफोर्ट एलेन्सिया परियोजना के प्रमोटर के विरुद्ध कड़ा कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के अंतर्गत 10 लाख रुपये का आर्थिक दंड अधिरोपित किया है।

प्रकरण की सुनवाई के दौरान यह पाया गया कि परियोजना में विकास कार्य नगर तथा ग्राम निवेश विभाग (टाउन एंड कंट्री प्लानिंगङ्क ङ्क×ष्टक्क) द्वारा स्वीकृत ले-आउट के अनुरूप नहीं किया गया। स्वीकृत ले-आउट से हटकर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया गया, जो रेरा अधिनियम की धारा 14(1) का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त धारा के अनुसार, किसी भी रियल एस्टेट परियोजना का विकास सक्षम प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित रेखांकन, ले-आउट एवं विनिर्देशों के अनुसार ही किया जाना अनिवार्य है।

प्राधिकरण ने यह भी संज्ञान में लिया कि वर्तमान में उक्त स्ङ्कक्का उपयोग परियोजना के आबंटितियों द्वारा किया जा रहा है। आबंटितियों के हितों और सार्वजनिक उपयोग को प्रभावित न करने के उद्देश्य से इस स्तर पर स्ङ्कक्का को ध्वस्त करने अथवा पुनर्निर्माण संबंधी कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है।

हालांकि, स्वीकृत ले-आउट से किए गए इस विचलन को गंभीर उल्लंघन मानते हुए प्राधिकरण ने प्रमोटर को उत्तरदायी ठहराया है और रेरा अधिनियम की धारा 14(1) के उल्लंघन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

छत्तीसगढ़ रेरा ने पुनः स्पष्ट किया है कि स्वीकृत ले-आउट अथवा योजनाओं से बिना सक्षम प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति के किया गया कोई भी परिवर्तन गंभीर उल्लंघन की श्रेणी में आता है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

खास खबर

प्रशासन की बड़ी कार्रवाई : आधी रात 25 किमी पीछा कर पकड़ा धान से लदा ट्रक

बलरामपुर-रामानुजगंज। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में कलेक्टर राजेंद्र कटारा के निर्देशन पर धान के अवैध परिवहन के खिलाफ प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। शासन के निर्देशानुसार अवैध धान परिवहन और भंडारण में संलिप्त कोचियों व बिचौलियों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अनुविभाग वाड्रफनगर क्षेत्र में गत मध्यरात्रि एक बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें गिरवानी मार्ग से उत्तर प्रदेश की ओर अवैध रूप से धान का परिवहन कर रहा एक ट्रक पकड़ा गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, ट्रक में लगभग 750 बोरी धान लदी थी, जिसे बिना किसी वैध दस्तावेज के ले जाया जा रहा था। मध्यरात्रि बैरियर ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों द्वारा ट्रक को रोकने का प्रयास किया गया, तो चालक वाहन लेकर फरार हो गया। इसकी सूचना मिलते ही अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नीर निधि नंदेहा के निर्देशन में तहसीलदार वाड्रफनगर, तहसीलदार रघुनाथनगर, नायब तहसीलदार और पुलिस बल की संयुक्त टीम गठित की गई। प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने रात में ही सघन सर्च अभियान चलाया। करीब 25 किलोमीटर क्षेत्र में विभिन्न मार्गों और गांवों में गहन जांच की गई। लगातार प्रयासों के बाद पेंडारी क्षेत्र में अवैध धान से लदा ट्रक पकड़ लिया गया।

अवैध डीजल भंडारण पर पुलिस की कार्रवाई, 1080 लीटर डीजल जब्त

रायपुर। राजधानी रायपुर में पुलिस ने अवैध रूप से डीजल का भंडारण करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई 05 जनवरी 2026 को पुलिस चौकी सिलतरा की टीम द्वारा की गई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान उमेश साव के रूप में हुई है, जो धनेली विधानसभा रोड स्थित दुर्गा ट्रेडर्स यार्ड का संचालक है। सूचना मिलने पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश और चौकी प्रभारी सिलतरा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने यार्ड में दबिश दी। रेड के दौरान आरोपी मौके पर मौजूद मिला। पूछताछ में उसने स्वयं को यार्ड का संचालक बताया। तलाशी लेने पर यार्ड में अलग-अलग प्लास्टिक ड्रमों में भारी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ डीजल भरा पाया गया। पुलिस द्वारा वैध दस्तावेज मांगे जाने पर आरोपी कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका और टीम को गुमराह करने का प्रयास करता रहा। पुलिस ने मौके से 6 प्लास्टिक ड्रमों में रखा कुल 1080 लीटर डीजल जब्त किया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1 लाख 440 रुपये बताई गई है।

धान खरीदी केन्द्र में 6 करोड़ से ज्यादा का घोटाला 6 पर एफआईआर, फड़ प्रभारी गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज

जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के धान खरीदी केंद्र में खरीफ विपणन साल 2024-25 के दौरान बड़ी अनियमितता सामने आई है। जहां करीब 6 करोड़ 55 लाख रुपए की आर्थिक गड़बड़ी पाई गई है। जब अपेक्स बैंक के नोडल अधिकारी ने मौके का निरीक्षण किया तो मामले का खुलासा हुआ। मामला आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित कोनपारा (पंजीयन क्रमांक 128) के अंदर संचालित धान खरीदी उपकेंद्र का है। यहां पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों ने धान खरीदी के रिकॉर्ड में हेराफेरी की है। शुरुआती जांच और संयुक्त जांच दल की ओर से किए गए भौतिक सत्यापन में 20,586.88 क्विंटल धान कम पाया गया। नोडल अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामला तुमला थाना क्षेत्र का है।

इस मामले में 2.01.26 को प्रार्थी राम कुमार यादव उम्र 61 वर्ष, नोडल अधिकारी छ ग राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स) के द्वारा थाना

तुमला में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित कोनपारा पंजीयन क्रमांक 128 के धान खरीदी उपकेंद्र में क्रमशः 1. भुनेश्वर यादव (खरीदी केंद्र के प्राधिकृत अधिकारी),2. जयप्रकाश साहू (समिति प्रबंधक),3. शिशुपाल यादव (फड़ प्रभारी),4. जितेंद्र साय(कंप्यूटर ऑपरेटर),5. अविनाश अवस्थी (सहायक फड़ प्रभारी),6. चंद्र कुमार यादव (उप सहायक फड़ प्रभारी) के द्वारा खरीफवर्ष 2024-25 में धान खरीदी कार्य में अनियमितता कर शासन को करोड़ों रुपए की क्षति पहुंचाई गई है। केंद्र के कम्प्यूटर में दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार उक्त खरीफवर्ष 2024-25 में कुल 1 लाख 61 हजार 250 क्विंटल की धान खरीदी की गई थी, जबकि खरीदी केंद्र के द्वारा मिल व संग्रहण केंद्रों में कुल 1 लाख 40 हजार 663 क्विंटल,12 किलोग्राम धान को परिदान किया गया था।

खरीदी केंद्र के पत्रक अनुसार कुल 20,586.88 क्विंटल धान की परिदान हेतु कमी पाई गई थी, जिसके सम्बन्ध में संयुक्त जांच दल के द्वारा भौतिक सत्यापन भी कराया गया था, मौके पर धान उपलब्ध नहीं था, जांच दल की रिपोर्ट में भी कुल 20,586.88 क्विंटल धान की कमी पाई गई,। उक्त कृत्य के कारण प्रति क्विंटल 3100 रु के हिसाब से कुल 20,586.88 क्विंटल धान में 6 करोड़ 38 लाख 19 हजार 328 रु व धान पैकिंग हेतु नए पुराने कुल 4,898 नग बारदाने जिनकी कुल कीमत 17 लाख 07 हजार 651 रु, इस प्रकार दोनों को मिलकर 6 करोड़ 55 लाख 26 हजार 979 रुपए की शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई गई है। अतः समिति स्तर पर धान खरीदी उप केंद्र कोनपारा के प्रभारी अधिकारी, फड़ प्रभारी, सहायक फड़ प्रभारी, उप सहायक फड़ प्रभारी व कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा मिली भगत कर , हेराफेरी करते हुए शासन को कुल 6करोड़ 55 लाख 26 हजार 979 रुपए की आर्थिक क्षति पहुंचाई गई है।

पुलिस के द्वारा छ ग राज्य सहकारी बैंक मर्यादित(अपेक्स) जशपुर के नोडल अधिकारी की रिपोर्ट पर धान खरीदी उप केंद्र कोनपारा के संदिग्ध क्रमशः 1. भुनेश्वर यादव (खरीदी केंद्र के प्राधिकृत अधिकारी),2. जयप्रकाश साहू (समिति प्रबंधक),3. शिशुपाल यादव (फड़ प्रभारी),4. जितेंद्र साय(कंप्यूटर ऑपरेटर),5. अविनाश अवस्थी (सहायक फड़ प्रभारी),6. चंद्र कुमार यादव (उप सहायक फड़ प्रभारी) के विरुद्ध बी एन एस की धारा 318(4), 320,336,338 व 61 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान पुलिस के द्वारा कार्यवाही करते हुए संदिग्ध आरोपियों में से एक धान खरीदी उप केंद्र कोनपारा के फड़ प्रभारी शिशुपाल यादव उम्र 39 वर्ष, निवासी ग्राम झारमुंडा थाना तुमला जिला जशपुर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। मामले से जुड़े अन्य आरोपी फरार हैं, पुलिस के द्वारा उनकी पातासाजी की जा रही है, जिन्हें भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जावेगा। मामले में पुलिस की अग्रिम जांच जारी है। मामले की कार्यवाही व आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी तुमला निरीक्षक कोमल सिंह नेताम, सहायक उप निरीक्षक टेकराम सारथी, प्रधान आरक्षक फ्रांसिस बेक, आरक्षक दुर्योधन यादव, अजीत लाल टोप्पो व महिला आरक्षक बीरजिनिया टोप्पो की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह ने बताया कि अपेक्स बैंक जशपुर के नोडल अधिकारी की रिपोर्ट पर, खरीफवर्ष 2024-25 में, तुमला क्षेत्रांतर्गत धान खरीदी उप केंद्र कोनपारा के अधिकारी/कर्मचारियों के द्वारा करोड़ों रुपए की धान खरीदी की अनियमितता के संबंध में पुलिस ने एफआई आर दर्ज कर लिया है, मामले से जुड़े फड़ प्रभारी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है, शेष आरोपी फरार है, जिनकी पता साजी की जा रही है, जिन्हें शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जावेगा, मामले में पुलिस की जांच जारी है।

सुरक्षाबलों की बड़ी सफलता : सुकमा में नक्सलियों के हथियारों और विस्फोटकों का बड़ा जखीरा बरामद

श्रीकंचनपथ न्यूज

सुकमा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। जिले के केरलापाल थाना अंतर्गत नवीन कैंप गोगुंडा क्षेत्र में सुरक्षाबलों ने नक्सल विरोधी अभियान के दौरान जंगल और पहाड़ी इलाकों में छिपाकर रखे गए नक्सलियों के एक बड़े डम्प को बरामद किया है। सुरक्षाबलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से छुपाए गए इस डंप में भारी मात्रा में हथियार व विस्फोटक बराम किया गया है।

बता दें वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार चलाए जा रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत सुकमा में पुलिस बल की टीम ने पांच जनवरी 2026 को नवीन कैंप गोगुंडा से सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। दुर्गम जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों की तलाशी के दौरान, सुरक्षाबलों ने नक्सलियों द्वारा छुपाए गए हथियारों, गोला-बारूद, विस्फोटकों और दैनिक उपयोग की सामग्री का एक बड़ा जखीरा बरामद किया। समय रहते की गई इस कार्रवाई से माओवादियों के हिंसक मंसूबों को नाकाम कर दिया गया।

सुरक्षाबलों द्वारा बरामद की गई यह सामग्री: बरामद सामग्री में देशी कट्टा, .315 राइफल के जिंदा राउंड, .303 के जिंदा राउंड चार्जर सहित, 12 बोर के जिंदा राउंड, टेलिस्कोप (डे-विजन एसएसआर), गन पाउडर काला व सफेद, जिलेटिन रड, इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, नकली वर्दी, कॉर्डेक्स वायर, बिजली तार, सेट चार्जर, मोटोरोला वॉकी-टॉकी बैटरी, वायरलेस एंटीना, मल्टीमीटर, कैलकुलेटर, स्विच, राइफल स्लिंग, पिट्ठू, पोच, नक्सल साहित्य, स्टील टिफिन, ड्रम, काला कपड़ा तथा अन्य भारी मात्रा में दैनिक उपयोगी सामग्री शामिल है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जिले में लगातार चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियानों से नक्सली संगठन को भारी नुकसान पहुंच रहा है। सुरक्षाबलों का मानना है कि माओवादियों के पास अब हिंसा छोड़कर शांति और विकास के मार्ग को अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।

सुरक्षाबल जिले में आगे भी नियमित रूप से सर्चिंग और ऑपरेशन जारी रखेंगे। इस सफल कार्रवाई ने क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के प्रति सुरक्षाबलों की प्रतिबद्धता को एक बार फिर साबित किया है।

5 लाख की इनामी महिला नक्सली भूमिका ने किया सरेंडर धमतरी में एसपी के समक्ष किया आत्मसमर्पण

श्रीकंचनपथ न्यूज

धमतरी। छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति तथा धमतरी पुलिस द्वारा लगातर किए जा रहे ऑपरेशन, सिविक एक्शन से प्रभावित होकर, नगरी एरिया कमेटी सदस्य एवं गोबरा एलओएस कमांडर भूमिका उर्फ गीता उर्फ लता उर्फ सोमारी (उम्र 37 वर्ष) ने सरेंडर कर दिया है। पुसनार गांव थाना गुंगालुर जिला बीजापुर की मूल निवासी भूमिका ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र कुमार पांडेय के समक्ष आत्मसमर्पण किया।

माओवादी उन्मूलन अभियान के तहत पुलिस मुख्यालय के सतत मार्गदर्शन और पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज अमरेश कुमार मिश्रा के निर्देशन में यह आत्मसमर्पण संपन्न कराया गया है। माओवादी संगठन में लंबे समय तक रहने के दौरान दाम्पत्य एवं पारिवारिक जीवन से वंचित रहने भेदभावपूर्ण व्यवहार तथा संगठन की विचारधारा से निराश और क्षुब्ध होकर उसने मुख्यधारा से जुड़ने का निर्णय लिया। शासन द्वारा उस पर 5 लाख रूपये का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण करने पर शासन की नीति के तहत उसे 50,000 रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है।

2005 से माओवादी संगठन में सक्रिय: भूमिका उर्फ गीता वर्ष 2005 से माओवादी संगठन में सक्रिय रही। प्रारंभिक प्रशिक्षण के पश्चात वह 2010 तक प्लाटून-01 में रही। वर्ष 2010 में उड़ीसा राज्य कमेटी में स्थानांतरित होकर विभिन्न कमेटियों में सक्रिय रहकर 2011 से 2019 तक सीसीएम संग्राम की गार्ड रही। इसके बाद 2019 से 2023 तक सीनापाली एरिया कमेटी में एसीएम तथा सितंबर 2023 में गोबरा एलओएस कमांडर के रूप में कार्यरत रही। वर्तमान में संगठन में सदस्यों की संख्या कम होने के कारण वह नगरी एवं सीतानदी एरिया कमेटी के साथ संयुक्त रूप से सक्रिय थी।

वर्ष 2010 - ओडिशा के पड़कीपाली (जिला महासमुंद) में हुई मुठभेड़ में 08 नक्सली मारे गए, इस दौरान एक ग्रामीण की मृत्यु हो गई तथा एक नक्सली लापता हो गया।

वर्ष 2014 - मैनपुर के मोतिपानी जंगल में हुई मुठभेड़ में शामिल रही, जिसमें किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।

वर्ष 2016 - नुआपाड़ा (ओडिशा) के कमलावाड़ी जंगल में हुई मुठभेड़ में शामिल रही, जिसमें कोई नुकसान नहीं हुआ।

इसी वर्ष नुआपाड़ा (ओडिशा) के पोतेलपाड़ा जंगल में हुई एक अन्य मुठभेड़ में भी शामिल रही, जिसमें किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।

वर्ष 2018 - जिला बीजापुर के तिमेनार जंगल में घर लौटते समय हुई मुठभेड़ में शामिल रही, जिसमें 08 नक्सली मारे गए।

वर्ष 2023 - गरियाबंद के ताराझार जंगल में हुई मुठभेड़ में शामिल रही, जिसमें कोई नुकसान नहीं हुआ।

वर्ष 2024 - धमतरी के एकावरी जंगल में हुई मुठभेड़ में शामिल रही, जिसमें किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।

वर्ष 2025 - धमतरी के मांदागिरी जंगल में हुई मुठभेड़ में शामिल रही, जिसमें कोई नुकसान नहीं हुआ।

10.11.2025 - गरियाबंद के सेमरा जंगल में हुई मुठभेड़ में शामिल रही, जिसमें किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति, बालोद, जिला बालोद (छ.ग.)

Pho.No.07749-296102,e-mail add.-maddi-balod.cg@nic.in, mandibalod.cg@gmail.com

क्र./ मंडी/ निर्माण शाखा / 2025-26/1416 — बालोद, दिनांक 06/01/2026

// मैनुअल निविदा आमंत्रण सूचना //

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति बालोद, जिला -बालोद (छ.ग.) के अंतर्गत निम्न दर्शित कार्य / स्थल एवं कार्य के सम्मुख दर्शित लागत अनुसार कार्य कराये जाने हेतु छ.ग. लोक निर्माण विभाग में एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से मुहरबंद निविदायें केवल पंजीकृत डाक से चार लिफाफा पद्धति से दि 20.02.2026 को 5.30 बजे तक **छ.ग. शासन लो.नि.वि. भवन कार्य हेतु दिनांक 01.01.2015, सड़क / ब्रिज कार्य हेतु दिनांक 01.01.2025 एवं विद्युत कार्य हेतु दिनांक 01.07.2015** से प्रभावशील एस.ओ.आर. एवं इस निविदा के जारी दिनांक तक संशोधित दर अनुसूची के आधार पर निविदा प्रपत्र-अ (प्रतिशत दर) में सचिव, कृषि उपज मंडी समिति बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.) में आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाएं इस कार्यालय में उपस्थित ठेकेदारों / प्रतिनिधियों के समक्ष **दिनांक 28.02.2026 को दोपहर 02.00 बजे** खोली जायेगी।

1. निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि :- **20.02.2026 को सायं 05.30 बजे तक**
2. निविदा प्रपत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि :- **27.02.2026 को सायं 05.30 बजे तक**
3. निविदा प्रपत्र खोले जाने की अंतिम तिथि :- **28.02.2026 को दोपहर 02.00 बजे तक**

क्र.	कार्य का नाम एवं स्थल	SOR पर अनु. लागत (लाख में)	ब्याने की राशि FDR में	ठेकेदार की श्रेणी	कार्यावधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	दर अनुसूचि
1	जिला बालोद वि.खं. गुण्डरदेही अंतर्गत ग्राम पंचायत चिचलगोंदी में निषाद पारा के सामुदायिक भवन के सामने शेड निर्माण कार्य	4.81	4000/-	डी एवं उच्च	03 माह वर्षा ऋतु सहित	1000/-	CG PWD Building works with effect from 01.01.2015 & Electrification works w.e.f. 01.07.2015 & CGPWD Road/ Bridge SOR w.e.f. 01.01.2025
2	जिला बालोद वि.खं. डौण्डीलोहारा अंतर्गत ग्राम पंचायत अहिबरन नवागांव में मंच के सामने शेड निर्माण कार्य	4.81	4000/-	डी एवं उच्च	03 माह वर्षा ऋतु सहित	1000/-	
3	जिला बालोद वि.खं. डौण्डीलोहारा के ग्राम पंचायत डेंगरापार में हरदेवलाल बाबा परिसर में शेड एवं आहाता निर्माण कार्य	4.81	4000/-	डी एवं उच्च	03 माह वर्षा ऋतु सहित	1000/-	
4	जिला बालोद वि.खं. डौण्डीलोहारा के ग्राम पंचायत भेडी (सु) में मंच के सामने बाजार चौक में शेड निर्माण कार्य	4.81	4000/-	डी एवं उच्च	03 माह वर्षा ऋतु सहित	1000/-	
5	जिला बालोद वि.खं. गुण्डरदेही के ग्राम पंचायत बोरगहन (अ) में सामुदायिक भवन साहू पारा शेड निर्माण कार्य	4.81	4000/-	डी एवं उच्च	03 माह वर्षा ऋतु सहित	1000/-	
6	जिला बालोद वि.खं. गुण्डरदेही अंतर्गत ग्राम पंचायत कांदूल में मंच के सामने शेड निर्माण कार्य	4.81	4000/-	डी एवं उच्च	03 माह वर्षा ऋतु सहित	1000/-	
7	जिला बालोद वि.खं. गुण्डरदेही अंतर्गत ग्राम पंचायत खर्रा में मंच के सामने शेड निर्माण कार्य	4.81	4000/-	डी एवं उच्च	03 माह वर्षा ऋतु सहित	1000/-	
8	जिला बालोद वि.खं. गुण्डरदेही अंतर्गत ग्राम पंचायत हल्दी में सामुदायिक भवन सिन्हा पारा में शेड निर्माण कार्य	4.81	4000/-	डी एवं उच्च	03 माह वर्षा ऋतु सहित	1000/-	
9	जिला बालोद वि.खं. गुण्डरदेही अंतर्गत ग्राम पंचायत बेलौदी गायत्री मंदिर के पास शेड निर्माण कार्य	4.81	4000/-	डी एवं उच्च	03 माह वर्षा ऋतु सहित	1000/-	
10	जिला बालोद वि.खं. डौण्डीलोहारा अंतर्गत ग्राम पंचायत टटेंगा में मंच के सामने बाजार स्थल में शेड निर्माण कार्य ।	9.67	4000/-	डी एवं उच्च	03 माह वर्षा ऋतु सहित	1000/-	
11	जिला बालोद वि.खं. डौण्डीलोहारा अंतर्गत ग्राम पंचायत सम्बलपुर (क) के ग्राम कन्याडबरी में कला मंच के सामने शेड निर्माण कार्य ।	4.81	4000/-	डी एवं उच्च	03 माह वर्षा ऋतु सहित	1000/-	
12	जिला बालोद वि.खं. गुण्डरदेही अंतर्गत ग्राम पंचायत किलेपार के ग्राम हीरूखपरी में कला मंच के सामने शेड निर्माण कार्य ।	4.81	4000/-	डी एवं उच्च	03 माह वर्षा ऋतु सहित	1000/-	
13	जिला बालोद वि.खं. गुण्डरदेही अंतर्गत ग्राम पंचायत खेरूद में सामुदायिक भवन के सामने साहू पारा में शेड निर्माण कार्य ।	4.81	4000/-	डी एवं उच्च	03 माह वर्षा ऋतु सहित	1000/-	CG PWD Building works with effect from 01.01.2015 & Electrification works w.e.f. 01.07.2015 & CGPWD Road/ Bridge SOR w.e.f. 01.01.2025
14	जिला बालोद वि.खं. डौण्डीलोहारा अंतर्गत ग्राम पंचायत भीमकन्हार में आदिवासी भवन के पास शेड निर्माण कार्य ।	4.81	4000/-	डी एवं उच्च	03 माह वर्षा ऋतु सहित	1000/-	
15	जिला बालोद वि.खं. गुण्डरदेही अंतर्गत ग्राम पंचायत कमरौद में कला मंच के सामने शेड निर्माण कार्य।	4.81	4000/-	डी एवं उच्च	03 माह वर्षा ऋतु सहित	1000/-	
16	जिला बालोद वि.खं. डौण्डीलोहारा अंतर्गत ग्राम पंचायत संबलपुर (क) में कला मंच के सामने शेड निर्माण कार्य ।	4.81	4000/-	डी एवं उच्च	03 माह वर्षा ऋतु सहित	1000/-	
17	जिला बालोद वि.खं. गुण्डरदेही अंतर्गत ग्राम पंचायत सिकोसा में रेलवे पारा मंच के सामने शेड निर्माण कार्य ।	4.81	4000/-	डी एवं उच्च	03 माह वर्षा ऋतु सहित	1000/-	
18	जिला बालोद वि.खं. गुण्डरदेही अंतर्गत ग्राम पंचायत बासीन में मंच के सामने शेड निर्माण कार्य ।	4.81	4000/-	डी एवं उच्च	03 माह वर्षा ऋतु सहित	1000/-	
19	जिला बालोद वि.खं. गुण्डरदेही अंतर्गत नगर पंचायत अर्जुन्दा में सतनाम भवन के सामने शेड निर्माण कार्य ।	4.81	4000/-	डी एवं उच्च	03 माह वर्षा ऋतु सहित	1000/-	
20	जिला बालोद वि.खं. गुण्डरदेही अंतर्गत अर्जुनी टिकरी में मंगल भवन के सामने (सतनाम पारा) शेड निर्माण कार्य ।	4.81	4000/-	डी एवं उच्च	03 माह वर्षा ऋतु सहित	1000/-	
21	जिला बालोद वि.खं. गुण्डरदेही अंतर्गत ग्राम पंचायत सलौनी के ग्राम फुलझर में कला मंच के सामने शेड निर्माण कार्य ।	4.81	4000/-	डी एवं उच्च	03 माह वर्षा ऋतु सहित	1000/-	
22	जिला बालोद वि.स.क्षे. गुण्डरदेही वि.खं. गुण्डरदेही अंतर्गत धान उपार्जन केन्द्र बेलौदी में चबूतरा शेड निर्माण कार्य ।	9.67	7500/-	डी एवं उच्च	03 माह वर्षा ऋतु सहित	1000/-	
23	जिला बालोद वि.स.क्षे. गुण्डरदेही वि.खं. गुण्डरदेही अंतर्गत धान उपार्जन केन्द्र बेलौदी में सी.सी. रोड निर्माण कार्य ।	8.24	6500/-	डी एवं उच्च	03 माह वर्षा ऋतु सहित	1000/-	

1. नियम व शर्तें एवं कार्य से संबंधित जानकारी कार्यालय में कार्यालयीन समय में **दिनांक 20.02.2026 तक** देखें / प्राप्त किये जा सकते है।

सचिव
कृषि उपज मंडी समिति
बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.)

भारसाधक अधिकारी / अपर कलेक्टर
कृषि उपज मंडी समिति
बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.)

सं.-46466/3

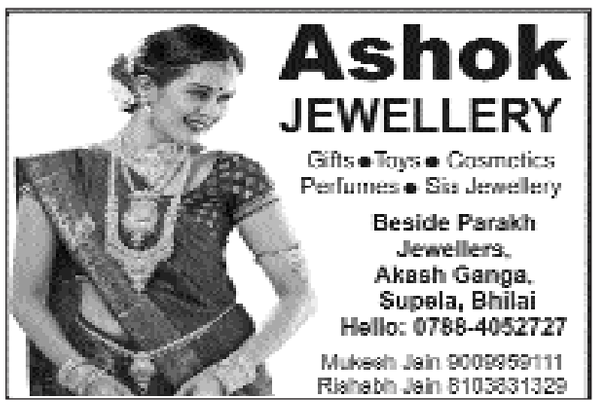

न्यायधानी बिलासपुर के समग्र विकास और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार को लेकर हुई व्यापक चर्चा

शहरों के संतुलित, समावेशी और योजनाबद्ध विकास को लेकर सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री साय

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में बिलासपुर नगर निगम एवं आसपास के क्षेत्रों के विकास को लेकर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बिलासपुर शहर तथा बाह्य क्षेत्रों में संचालित एवं प्रस्तावित विकास कार्यों, मूलभूत सुविधाओं के विस्तार और निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायधानी बिलासपुर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और बढ़ते शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए यहां संतुलित, समावेशी और योजनाबद्ध विकास आवश्यक है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ तेजी से विकास की ओर अग्रसर है और इसी के अनुरूप शहरी अधोसंरचना को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी प्रगतिरत योजनाओं को तय समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से स्वच्छ एवं नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने और इससे जुड़ी परियोजनाओं पर गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिलासपुर को उद्योग एवं पर्यटन की दृष्टि से प्राथमिकता में रखते हुए विकास की योजनाएं तैयार की जाएं।

श्री साय ने बताया कि पिछले दो वर्षों में सरकार द्वारा निरंतर नए विकास कार्यों को स्वीकृति दी गई है। साथ ही आने वाला बजट भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगा और इसके माध्यम से विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना भी साकार होगी। उन्होंने कहा कि विभागों के आपसी समन्वय से ही बेहतर परिणाम सामने आएंगे और गांवों के साथ-साथ शहरों के विकास में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी।

बैठक में सड़क, पुल-पुलिया, पेयजल, ड्रेनेज, प्रदूषण मुक्त शहर, यातायात व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल एवं युवा कल्याण, आवास, ई-बस सेवा, हवाई यातायात, ट्रांसपोर्ट नगर, उद्योग एवं व्यापार, पर्यटन तथा अरपा विशेष क्षेत्र विकास परियोजना (अरपा साडा) से जुड़े विषयों पर बिंदुवार मंथन किया गया और विभिन्न विषयों पर सहमति भी बनी। इसमें सिम्स के नए अस्पताल भवन के लिए एएस जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल को पीपीपी मोड पर संचालित करने का निर्णय लिया गया। बिलासपुर एयरपोर्ट के विस्तार हेतु डिफेंस को राशि हस्तांतरित किए जाने की जानकारी दी गई, जिस पर जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। साथ ही एयरपोर्ट के अन्य विकास कार्यों एवं नाइट लैंडिंग सुविधा को शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए गए। ट्रांसपोर्ट नगर सिलपहरी के विकास का कार्य सीएसआईडीसी द्वारा किए जाने तथा भूमि हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर सहमति बनी। उसलापुर रेलवे ओवरब्रिज के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने और इसे आगामी बजट में शामिल करने का निर्णय लिया गया।

इसके अतिरिक्त बिलासपुर के राजीव गांधी चौक, नेहरू चौक, महामाया चौक (वाय आकार) - रतनपुर मार्ग तक 305 करोड़ की लागत से फ्लाई ओवर ब्रिज निर्माण, पुराना बस स्टैंड चौक पर सीएमडी चौक-इमलीपारा रोड-टैगोर चौक-जगमल चौक तक 115 करोड़ की लागत से फ्लाई ओवर का निर्माण, एफसीआई गोडाउन व्यापार विहार क्षेत्र को सिरगिट्टी-महमंद बायपास से जोड़ने हेतु 320 करोड़ की लागत से तारबहार फ्लेरलेन रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार शहर के यातायात दबाव को कम करने हेतु 950 करोड़ की लागत से फ्लेरलेन बिलासपुर रिंग रोड निर्माण के लिए एनएचएआई की सहमति के आधार पर लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्ताव भेजने पर सहमति बनी।

खारंग जलाशय में पाराघाट व्यपवर्तन योजना के लिए 328 करोड़ रुपये, नगर निगम क्षेत्र में अरपा नदी के एसटीपी एवं ड्रेनेज कार्यों के लिए 252 करोड़ रुपये तथा बिलासपुर शहर की जलभराव समस्या के समाधान हेतु आपदा प्रबंधन निधि से 150 करोड़ रुपये दिए जाने की सहमति बनी। बिलासपुर में कैंसर अस्पताल के लिए टाटा मेमोरियल अस्पताल से चर्चा करने, कानन पेंडारी के सामने अंडरपास निर्माण, कोनी से बिरकोना-खमतराई-बहतराई मार्ग के निर्माण, 24म7 जल आपूर्ति योजना हेतु डीपीआर तैयार करने तथा अरपा साडा क्षेत्र के विकास के लिए टीएनसीपी एवं जिला अधिकारियों की बैठक कर पूर्व योजनाओं पर चर्चा तथा इसे आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, विधायक अमर अग्रवाल, विधायक सुशांत शुक्ला, विधायक धरमलाल कौशिक, महापौर पूजा विधानी, मुख्य सचिव विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह तथा विभिन्न विभागों के सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

स्वामी विवेकानंद ने दुनिया में बढ़ाया भारत की संस्कृति एवं सनातन का मान : सीएम साय

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने अल्पायु में ही संपूर्ण विश्व को भारत की सनातन संस्कृति, अध्यात्म और दर्शन से परिचित कराते हुए देश का सम्मान बढ़ाया था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज शाम राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित सेंड ऑफसेरेमनी समारोह में युवाओं को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम का आयोजन खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा किया गया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस पर प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है तथा राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन किया जाता है। यह उत्सव भारत की युवा ऊर्जा, रचनात्मकता और राष्ट्र निर्माण की भावना का सशक्त प्रतीक है।

उन्होंने कहा कि हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि स्वामी विवेकानंद जी ने अपना अधिकांश समय रायपुर में बिताया। बूढ़ा तालाब एवं डे-भवन जैसी पावन स्थलों की स्मृतियाँ आज भी युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बनी हुई हैं।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इस वर्ष राष्ट्रीय युवा उत्सव में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने के लिए 75 प्रतिभाशाली युवाओं का चयन किया गया है, जो पूरे राज्य के लिए गौरव की बात है। इनमें 45 युवा विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग से, 1 युवा डिजाइन फॉर भारत ट्रैक से तथा 29 प्रतिभागी सांस्कृतिक ट्रैक्स से शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय युवा उत्सव में छत्तीसगढ़ के युवाओं का प्रतिनिधित्व भारत की युवा शक्ति, रचनात्मकता, नेतृत्व क्षमता और विकसित भारत के संकल्प में सहभागी बनने का सुनहरा मौका है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवा राष्ट्रीय मंच पर छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति, लोकनृत्य, लोकगीत और युवा नेतृत्व का प्रदर्शन करेंगे। इससे छत्तीसगढ़ की मिट्टी की खुशबू पूरे देश में बिखरेगी और राज्य गौरवान्वित होगा। मुख्यमंत्री साय ने राष्ट्रीय स्तर पर चयनित सभी प्रतिभागियों को बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के युवा 9 जनवरी को नई दिल्ली पहुँचकर देश के विभिन्न प्रांतों से आए युवा कलाकारों एवं यंग लीडर्स से मुलाकात करेंगे और विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। 11 जनवरी को इसरो के गगनयात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से मिलेंगे और उनके अंतरिक्ष अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के युवा प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि युवा शक्ति राष्ट्र की पहचान है और युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के प्रसिद्ध संदेश उठो, जागो और तब तक नहीं रुको, जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए का उल्लेख करते हुए युवाओं से इससे प्रेरणा लेने का आह्वान किया।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि जहाँ युवा समूह होता है, वहाँ ऊर्जा का स्वाभाविक संचार होता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि देश के यंग लीडर्स सभी क्षेत्रों में नेतृत्व करें। हमारी सरकार ने बेहतर व्यवस्थाओं के साथ विकासखंड स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक युवा महोत्सव का सफल आयोजन कराया है। इसके लिए उन्होंने विभागीय अधिकारियों की सराहना भी की। श्री साव ने भी सभी चयनित प्रतिभागियों को बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने मुख्य मंच से चयनित प्रतिभागियों को वेशभूषा किट प्रदान किए। साथ ही कुछ प्रतिभागियों ने अपने अनुभव भी साझा किए।

इस मौके पर युवा आयोग अध्यक्ष विश्वविजय सिंह तोमर, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार सहित अन्य विभागीय अधिकारीगण एवं प्रतिभागी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

बस्तर अंचल का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध : साय

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मंत्रालय महानदी भवन, रायपुर में हमर छत्तीसगढ़ जन भ्रमण योजना के अंतर्गत राजधानी भ्रमण पर आए सुकमा जिले की सुदूरवर्ती ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री साय ने पंचायत प्रतिनिधियों से आत्मीय संवाद करते हुए उनका हालचाल जाना।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर अंचल का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं को बस्तर के प्रत्येक गांव तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से चर्चा के दौरान कहा कि राज्य सरकार बस्तर क्षेत्र में भी तीव्र गति से विकास कार्य संचालित कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुदूर अंचलों में सुरक्षा बलों के कैंप स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे विकास कार्यों को सुरक्षा और गति दोनों प्राप्त हो रही हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अब अधिकांश गांवों में शासकीय राशन दुकानों की स्थापना की जा चुकी है तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक प्रभावी रूप से पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में बस्तर क्षेत्र पूरी तरह नक्सलमुक्त होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आत्मनिर्भर बस्तर के लक्ष्य की दिशा में लगातार प्रयासरत है। इसी उद्देश्य से बस्तर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को राजधानी भ्रमण के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, ताकि वे यहां के विकास कार्यों को देखकर प्रेरित हों और अपने क्षेत्रों में भी चहुंमुखी विकास को बढ़ावा दें। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा एवं संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि हमर छत्तीसगढ़ जन भ्रमण योजना के अंतर्गत सुकमा जिले के सुदूरवर्ती विभिन्न ग्राम पंचायतों के लगभग 100 पंचायत प्रतिनिधि राजधानी रायपुर के दो दिवसीय भ्रमण पर आए हैं। भ्रमण के दौरान जनप्रतिनिधियों को मंत्रालय, जंगल सफारी, आदिवासी संग्रहालय, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और शॉपिंग मॉल जैसे महत्वपूर्ण स्थलों का अवलोकन कराया गया।

प्रत्येक माह के 7 तारीख को मनाया जाएगा आवास दिवस

श्रीकंचनपथ समाचार

जांजगीर-चांपा। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत प्रदेश में निर्धारित समय-सीमा में आवास निर्माण कार्य पूर्ण कराए जाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जनजागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक माह की 7 तारीख को ग्राम पंचायत स्तर पर आवास दिवस आयोजित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। यह आयोजन चावल महोत्सव एवं महात्मा गांधी नरेगा के रोजगार दिवस के साथ अनिवार्य रूप से किया जाएगा।

कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देशन एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गोकुल रावटे के मार्गदर्शन में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में आवास निर्माण से जुड़ी समस्याओं का त्वरित निराकरण, हितग्राहियों को प्रोत्साहन एवं योजना के प्रावधानों की जानकारी दी जाएगी। इस अवसर पर निम्न बिंदुओं पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्वीकृत, निर्माणाधीन एवं पूर्ण आवासों के हितग्राहियों की सूची का वाचन कर स्वीकृति प्रमाण पत्र का वितरण किया जाएगा। आवास निर्माण पूर्ण करने वाले हितग्राहियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। निर्धारित प्रगति के बाद भी लंबित किश्तों के प्रकरणों में ज्ञलब् पूर्ण कराकर 7 दिवस के भीतर राशि हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 90 दिवस की अकुशल मजदूरी राशि के भुगतान की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। आवास निर्माण में आ रही स्थानीय समस्याओं एवं बाधाओं का प्रत्येक माह 7 तारीख तक चरणबद्ध (2-2) निराकरण कर हितग्राहियों को अवगत कराया जाएगा। जिला एवं विकासखंड स्तर के अधिकारी-कर्मचारी इस कार्य की सतत समीक्षा करेंगे। सेंटरिंग प्लेट की उपलब्धता में आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु सभी भागीदारों, स्व-सहायता समूह सदस्यों के साथ सामूहिक चर्चा की जाएगी।

स्वर्ण पदक जीतने वाली कवर्धा की बेटी रिया का किया सम्मान

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। बिहार की राजधानी पटना में 25 से 29 दिसंबर तक आयोजित साउथ एशियन बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हाँसिल किया। इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत, नेपाल, भूटान और श्रीलंका सहित चार देशों की टीमों ने भाग लिया था।

इस चैंपियनशिप में भारत की विजेता टीम का हिस्सा बनकर देश और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने वाली कवर्धा की होनहार खिलाड़ी रिया तिवारी का

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सम्मान किया। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने रिया को स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र भेंट कर उनकी उपलब्धि की सराहना की तथा उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि रिया तिवारी की यह उपलब्धि न केवल कवर्धा जिले बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रिया ने यह सिद्ध कर दिया है कि प्रतिभा, अनुशासन और कठिन परिश्रम से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रिया भविष्य में भी देश के लिए अनेक पदक जीतेंगी और प्रदेश की नई पीढ़ी के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनेंगी। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने यह भी कहा कि राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए हरसंभव सहयोग प्रदान कर रही है। खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, सुविधाएं और प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं, ताकि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बना सकें। रिया ने कहा कि इस सफलता का पूरा श्रेय मेरे माता-पिता और मेरे कोच श्री अविनाश चौहान एवं श्री जय किशन को जाता है। उनके निरंतर मार्गदर्शन, अनुशासन और प्रेरणा के बिना यह उपलब्धि संभव नहीं हो पाती। हर कठिन समय में उन्होंने मेरा आत्मविश्वास बनाए रखा और मुझे आगे बढ़ने की शक्ति दी।

यह जीत मेरे लिए केवल एक पदक नहीं, बल्कि मेरे खेल जीवन की एक नई शुरुआत है। मैं आगे भी पूरे समर्पण और मेहनत के साथ देश और प्रदेश के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का प्रयास करूंगी

बस्तर अंचल के हर गांव तक विकास पहुंचाना है साय सरकार का संकल्प- मंत्री केदार कश्यप

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने बस्तर प्रवास के दौरान नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विकासखंडों में आयोजित भूमिपूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रमों में सहभागिता की। इस दौरान उन्होंने 24 करोड़ 53 लाख रुपये से अधिक की लागत के विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी।

वन मंत्री केदार कश्यप ने 24 करोड़ 53 लाख रुपये से अधिक के विकास कार्यों का किया भूमिपूजन

मंत्री कश्यप ने मर्दापाल क्षेत्र में जल संसाधन विभाग द्वारा स्टॉप डेम निर्माण, लोक निर्माण विभाग द्वारा मुख्य मार्गों के डामरीकरण, स्वास्थ्य विभाग द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण, तथा वन विभाग द्वारा देवगुड़ी संरक्षण एवं निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया। इसके साथ ही स्कूली छात्र-छात्राओं को साइकिल वितरण भी किया गया।

मंत्री कश्यप ने गोंदियापाल में 313.39 लाख रुपये की लागत से प्रस्तावित सड़क निर्माण (पुल-पुलिया सहित), मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत पुलिया निर्माण, बस्तर विकास प्राधिकरण द्वारा सी.सी. सड़क निर्माण तथा सामुदायिक भवन कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया। इसी प्रकार बड़ेआमाबाल एवं तारागांव में पुलिया निर्माण, 3.70 किलोमीटर सड़क निर्माण (पुल-पुलिया सहित), सी.सी. सड़क, अटल डिजिटल सुविधा केंद्र, मुक्तिधाम एवं प्रतीक्षालय शेड, जलाशय बांध पर गेट, स्पिलवे, नहर लाइनिंग एवं संरचना निर्माण, सोलर हाई मास्ट स्थापना तथा महातारी सदन का लोकार्पण किया गया।

मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि भाजपा सरकार के नेतृत्व में बस्तर निरंतर विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और सहकारिता के क्षेत्र में तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। मंत्री श्री कश्यप ने बताया कि सरकार द्वारा बस्तर क्षेत्र में 15 हजार प्रधानमंत्री आवास, 45 नए आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन, महातारी सदन एवं नए स्वास्थ्य केंद्रों को स्वीकृति दी गई है, जिससे गांव-गांव तक सुविधाएं पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए होटल मैनेजमेंट, फूड प्रोसेसिंग और डिजिटल मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

हर वर्ग के उत्थान के लिए सरकार संकल्पित

मंत्री कश्यप ने कहा कि किसान, मजदूर और महिला वर्ग सहित समाज के हर वर्ग को योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। भाजपा सरकार का उद्देश्य गरीबों और वंचितों को उनका अधिकार दिलाना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब हर गरीब परिवार को आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में महिलाओं और गरीबों के लिए विशेष योजनाएं लागू की जा रही हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सहायता योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

तेजी से हो रहे विकास कार्य

मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि छोटे-छोटे गांवों और पंचायतों में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सरस्वती साइकिल योजनाष् जैसी योजनाएं शामिल हैंए जो पात्र छात्रों को निःशुल्क साइकिल या उसके लिए नकद राशि प्रदान करती हैं ताकि वे स्कूल जा सकें और अपनी शिक्षा जारी रख सकेंए जिससे उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ती है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बच्चों को साइकिल वितरित की जा रही है, जिससे विशेष रूप से बेटियों को आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं। इन विकास कार्यों से क्षेत्र में अधोसंरचना, शिक्षा एवं सामाजिक विकास को नई दिशा मिलेगी।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक राजेश अग्रवाल द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित कर, 204 आकाशगंगा सुपेला, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक राजेश अग्रवाल shreekanchanpath2010@gmail.com, Mo - 9303289950